सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 325, नई दिल्ली । शनिवार, 01 फरवरी 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुला समर्थनः दिल्ली देहात
06 इतिहास लेखन में एआइ का उपयोग
08 बिना फिटनेस के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चल सकता....

दिल्ली में व्यवसायिक वाहनों के जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही परेशानियों से अब मिलेगा कुछ निजात

संजय बाटला

नई दिल्ली। परिवहन आयुक्त द्वारा एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बिना सोचे समझे और बिना पूर्ण जानकारी प्राप्त किए गए आदेश से दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधि में चालित वाहनो को वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने में जो असुविधा उत्पन्न हुई थी अब उससे कुछ निजात मिलने की संभावना बन गई है।

परिवहन आयुक्त को भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह ही अपना दिया गया आदेश आखिर में व्यवसायिक वाहनों को भुखमरी और कर्जदारी में डालने के बाद वापिस लेना पड़ा।

पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना फैसला बदला था और वाहनों की जांच झूलझूली से वापिस बुराड़ी जांच शाखा में शुरू करने के आदेश जारी किए थे और अब वहीं कार्य परिवहन आयुक्त द्वारा भी किया गया। जब पूर्व में ही यह सिद्ध हो चुका था की किसी भी हालात में झूलझूली वाहन जांच शाखा में इतने वाहनों की जांच संभव नहीं है तो आखिर क्यों उस समस्या का समाधान किए बिना परिवहन आयुक्त ने हठ दिखाते हुए वही आदेश जारी कर दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों को परेशानी उत्पन्न करवाई एक बड़ा सवाल है। पर अब अपने आदेश पर पुनः बदलाव कर उन्होंने दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत दी है। आज से बिना परमिट वाले व्यवसायिक वाहनों की जांच झूलझूली वाहन जांच शाखा से वापिस कर बुराड़ी वाहन जांच शाखा में शुरू कर दी गई है। इसी के साथ अन्य व्यवसायिक वाहन मालिकों को झूलझूली वाहन जांच शाखा में अपने वाहनों की जांच करवाने के लिए अपॉइंटमेंट मिलने की भी उम्मीद बढ़ गई है जिससे उन्हें भी अब समस्या से समाधान प्राप्त होने की उम्मीद जागी है पर परिवहन आयुक्त के हठ के कारण जितने वाहन बिना जांच प्रमाण पत्र हो गए थे उन्हें अभी भी कुछ समय और अपॉइंटमेंट प्राप्त होने में लग सकता है।

देर आए दुरुस्त आए कहावत यहां सही सिद्ध होती हैं।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

बदरीनाथ-केदारनाथ रेल नेटवर्क ने पकड़ी गति, अब कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए विशेष सहायता की दरकार

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तराखंड सरीखे पर्वतीय राज्य के लिए रेल परियोजनाएं ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एक बेहतर और श्रेष्ठ विकल्प माना जा रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन बनाने का काम जिस तेजी से चल रहा है, उससे राज्य की अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं।

चमोली। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम को रेल नेटवर्क से जोड़ने के प्रयासों के गति पकड़ने के बाद अब उत्तराखंड को उत्तरकाशी और बागेश्वर रेल परियोजनाओं में तेजी लाने की दरकार है। राज्य सरकार इस बार इन दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में विशेष सहायता मिलने की उम्मीद कर रही है। राज्य इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण में विशेष सहायता के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध कर चुका है। उत्तराखंड सरीखे पर्वतीय राज्य के लिए रेल परियोजनाएं ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एक बेहतर और श्रेष्ठ विकल्प माना जा रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन बनाने का काम जिस तेजी से चल रहा है, उससे राज्य की अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार चाहती है कि चारधाम रेल परियोजना के तहत बदरीनाथ-केदारनाथ के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी रेल लाइन से जुड़ें। इसलिए डोईवाला से उत्तरकाशी तक प्रस्तावित रेल परियोजना पर ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की तरह वित्तीय मंजूरी और तेज गति से इस पर काम शुरू होने की आवश्यकता महसूस जा रही है। इसी तरह बागेश्वर-टनकपुर ब्राड गेज रेल परियोजना के निर्माण में भी केंद्र से तेजी दिखाने की अपेक्षा की जा रही है। सामरिक महत्व इन परियोजनाओं के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तर्क है। सरकार चाहती है कि दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान हो, ताकि स्थानीय लोगों को परिवहन के सुगम साधन मिल सके। सचिव वित्त दिलीप जावलकर कहते हैं, हमने रेल कनेक्टिविटी की प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष अपने अपेक्षा रख दी है। हम इसके लिए केंद्रीय बजट से उम्मीद कर रहे हैं।

नोएडा के इस मेट्रो स्टेशन पर बनेंगे दो फुट ओवर ब्रिज, पैदल यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा प्राधिकरण ने बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास दो फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाने का फैसला किया है। इससे प्रतिदिन 80 हजार वाहनों की आवाजाही के बीच से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को राहत मिलेगी। एफओबी एमपी-3 रोड पर क्रासिंग के आसपास ही बनेंगे। प्राधिकरण की टीम ने पैदल यात्रियों के आने-जाने के समय व स्थान को लेकर अध्ययन शुरू कराया है।

नोएडा। बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन आने जाने के लिए प्रतिदिन लगने वाले यातायात जाम व तेज रफ्तार वाहनो के बीच से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को निजात दिलाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कवायद शुरू कर दी है। यहां रोजाना करीब 80 हजार वाहनों की आवाजाही रहती है। प्राधिकरण ने सेक्टर-37 क्रॉसिंग के आसपास दो फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाने का फैसला लिया है।

दोनों एफओबी एमपी-3 रोड पर क्रासिंग के आसपास ही बनेंगे। इसके लिए प्राधिकरण की टीम ने पैदल यात्रियों के आने जाने के समय व स्थान को लेकर अध्ययन शुरू कराया है। रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि किन दो स्थानों पर एफओबी बनाया जाए। प्राधिकरण सीईओ डॉ लोकेश एम ने बताया कि सेक्टर-37 क्रासिंग पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। हैवी ट्रैफिक फ्लो होता है।

यहां पर सड़क पार करने के लिए नहीं है कोई एफओबी

यहीं से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, कालिंदी कुंज दिल्ली, डीएससी रोड की ओर वाहन आते जाते हैं। इसी क्रॉसिंग पर बाटेनिकल मेट्रो स्टेशन भी है, जहां पर ब्लू लाइन व मजेंटा लाइन है। भविष्य में बाटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक एक्वा मेट्रो की लिंक लाइन प्रस्तावित है। इन कारणों से मुसाफिरों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वर्तमान में यहां सड़क पार करने के लिए कोई एफओबी नहीं है।

जान हथेली पर लेकर लोग हर दिन ट्रैफिक के बीच करते हैं रोड पार

ऐसे में जान हथेली पर लेकर प्रतिदिन लोग भारी यातायात के दबाव के बीच रोड पार करते हैं। वाहनों के लगातार चलते रहने की वजह से यातायात पुलिस की मदद से ही लोग सड़क पार कर पाते हैं। इस कारण यहां जाम भी लगता है। उन्होंने बताया कि इस रोड पर सेक्टर-37 फ्लाईओवर और मेट्रो लाइन है। इसलिए इसकी स्टडी कराई जा रही है कि कहा पर एफओबी बनाया जाए।

ताकि इसका लोग प्रयोग कर सकें। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि फ्लाईओवर और मेट्रो संचालन में कोई परेशानी न हो साथ ही नई लाइन का अलाइनमेंट भी चेक किया जाएगा। एक बार अध्ययन रिपोर्ट आने के बाद टेंडर जारी होगा।

रेल बजट में हो सकती है 15 फीसदी वृद्धि, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सुरक्षित सफर पर रहेगा जोर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे देश के विकास की गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पिलर के तौर पर देखा जाता है। इसलिए कुछ समय पहले तक रेलवे का अलग से बजट आता था। रेल बजट को आम बजट में शामिल करने का उद्देश्य यही था कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इसे ज्यादा पैसा दिया जा सके। एक्सपर्ट्स का मानना हे कि बजट 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण में निवेश के साथ ही सुरक्षित रेल यात्रा को सुनिश्चित करना एक बड़ा पहलू होगा। गौरतलब है कि 2023 में ओडिशा में हुई दुखद रेल दुर्घटना में 290 से अधिक लोगों की जान चली गई। 2024 की पहली छमाही में, तीन बड़ी दुर्घटनाएं हुईं - इनमें जून में कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट, जुलाई में बाराबांबू और गोंडा के पास ट्रेन का पटरी से उतरना शामिल हैं। इनमें 17 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए। इन हादसों को देखते हुए बजट में रेलवे संरक्षा को बढ़ाने और देशभर में कवच सिस्टम को लगाने के लिए ज्यादा बजट का ऐलान किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार रेलवे का बजट 15 से 20 फीसदी बढ़ सकता है। इस बार रेलवे को बजट में तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा मिल सकता है।

2024-25 के बजट में रेलवे को लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। बजट में ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें, नए ट्रैक, रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाना, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रैक को और बेहतर बनाना और रेलवे को कार्बन मुक्त या ग्रीन रेलवे बनाने के कदमों की संभावना है। माना जा रहा है इस बजट में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसा मिल सकता है। सरकार का जोर मुख्य रूप से राष्ट्रीय रेल योजना 2030 पर रहेगा। इस योजना का उद्देश्य रेलवे की परिचालन क्षमता एवं वाणिज्यिक नीति दोनों को बेहतर बनाने के लिए योजना को तैयार करना है। इसी आधार पर रेलवे की योजना माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना है। इसके लिए रेलवे की क्षमताओं का विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत रेल गाड़ियों की औसत स्पीड को भी बढ़ाया जाना है।

आधुनिकीकरण और संरक्षा के लिए मिलेगा ज्यादा पैसा

रेलवे बोर्ड में एडिशनल मेम्बर रहे विजय दत्त कहते हैं कि पिछले बजट में रेलवे को लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपये मिले थे। उम्मीद है कि इस बजट को बढ़ा कर लगभग 3 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 2019 में बजट के दौरान कहा था कि 2030 तक रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसी के तहत पिछले बजटों में भी रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अच्छा पैसा मिला है। आगे भी ऐसा होने की उम्मीद है। आज रेलवे के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आधुनिकीकरण के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करना है। वहीं सरकार भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने के लिए कई प्रयास कर रही है। जलवायु संकट को देखते हुए पूरी दुनिया में रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है।

भारतीय रेलवे मालभाड़े में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रही है। देश में 1950 में सिर्फ 20 फीसदी माल ही सड़कों के जरिए ले जाया जाता था वहीं आज आज देश में 95 फीसदी माल का परिचालन सड़क के जरिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के तहत एक बार फिर 45 फीसदी माल को रेल के जरिए ले जाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। रेलवे से माल का परिवहन किया जाना सस्ता भी है और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है। माल का परिवहन रेलवे के जरिए किए जाने के लिए बड़े पैमाने पर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। चीन में 1973 तक सिर्फ 45000 किलोमीटर रेलवे लाइनें थीं वहीं उस समय भारत में 65000 किलोमीटर रेल लाइन थी। लेकिन आज भारत में जहां लगभग 70 हजार किलोमीटर रेल लाइन है वहीं चीन अपनी रेल लाइनों को 1.21 लाख किलोमीटर तक बढ़ा चुका है। हमें तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए जरूरी है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया जाए और उम्मीद है कि इस बार बजट में भी सरकार भी इसी दिशा में कदम उठाएगी।

कश्मीर के लिए रेलगाड़ी चलाने की है तैयारी

भारतीय रेलवे कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने के लिए लगभग पूरी तैयारी कर चुका है। इसके लिए कभी भी ऐलान किया जा सकता है। उम्मीद है बजट में इस बारे में कुछ रूपरेखा प्रस्तुत की जाए। इस बार बजट में वित्त मंत्री स्लीपर डिब्बों वाली वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान कर सकती हैं। ये ट्रेनें लम्बी दूरी तक चलाई जा सकती हैं। इन ट्रेनों को पहले से चल रही राजधानी ट्रेनों वाले रूट पर भी चलाया जा सकता है।

आईसीएफ के पूर्व जीएम और वंदे भारत ट्रेन को बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुधांशु मणी कहते हैं कि सभी को उम्मीद है कि इस बार रेलवे का बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। अगले कुछ दिनों में स्लीपर वंदेभारत ट्रेन चलाने को लेकर ऐलान किया जा सकता है। ये ट्रेन बन कर तैयार है। सरकार को वंदे भारत ट्रेनें बनाने के साथ ही इसको इसकी पूरी क्षमता से चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की जरूरत है। इन ट्रेनों को फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलाया जा रहा है जबकि इन्हें 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड पर चलाया जा सकता है। सरकार को बड़े पैमाने पर ट्रैक का अपग्रेडेशन करने पर जोर देना चाहिए। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और सुरक्षित सफर के लिए जरूरी है कि देशभर के ट्रैक पर जल्द से जल्द कवच को पूरी तरह से लगाया जाए। दरअसल कवच देश में डेवलप किया गया ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इससे अगर एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने सामने हों तो कवच टेक्नोलॉजी ट्रेन की स्पीड कम कर ब्रेक लगाती है। इससे दोनों ट्रेनें टकराने से बच जाएंगी।

फ्रेट कॉरीडोर का काम तेज होगा

भारतीय रेलवे अपने माल भाड़ा कारोबार बढ़ाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरीडोर बनाने का काम लगभग पूरा कर चुकी है। डीएफसीसी के प्रबंध निदेशक रह चुके एके सचान कहते हैं कि डीएफसीसी के ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरीडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। सरकार अब देश की विभिन्न खदानों से भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर को जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। सरकार का जोर बेहतर रोलिंग स्टॉक बनाने पर भी है। इसमें भी आने वाले समय में बड़े पैमाने पर निवेश होने की संभावना है। रेलवे जल्द ही प्रयागराज में गंगा पर नया पुल बनाने की योजना पर काम कर रही है। जल्द ही इस पर भी काम शुरू होता देखा जा सकता है।

संरक्षा श्रेणी की एक लाख भर्तियां जल्द हों

ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा कहते हैं कि इस बार वित्त मंत्री से रेल कर्मियों को भी काफी उम्मीदें हैं। पिछले साल रेल हादसों ने स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे को संरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। रेलवे में लेवल 1 में संरक्षा कैटेगरी के एक लाख पद खाली हैं। रेलवे इन पदों को कम करने पर विचार कर रही है। लेकिन रेलवे को ये समझना होगा कि एक रेल कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर रेल यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। रेलवे में लेवल 1 में संरक्षा कैटेगरी के खाली पड़े एक लाख पदों पर तत्काल भर्ती किए जाने की जरूरत है। वहीं सबसे बड़ी जरूरत देश में सभी रूटों पर पूरी तरह कवच सिस्टम लगाए जाने की है जिससे एक तरफ जहां यात्रियों की यात्रा सुरक्षित होगी वहीं रेल कर्मियों को भी हादसों से बचाया जा सकेगा। बहुत से रेलवे स्टेशनों पर अभी भी बुनियादी यात्री सुविधाएं जैसे पानी, लाउंज, वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम आदि उपलब्ध नहीं हैं। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। रेलवे में स्टाफ बेनिफिट फंड के लिए प्रति व्यक्ति ग्रांट बढाई जाए। 2014 के बाद इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधाएं भी बढ़ाई जाने की जरूरत है। इसके लिए नए अस्पताल और डिस्पेंसरी खोलनी होगी।

कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव, कैरियर, रोग और उपाय

ज्योतिषाचार्य पंडित योगेश पौराणिक (इंजी.)

हमारे नक्षत्र मंडल में कृतिका नक्षत्र को सौर ऊर्जा का मूल स्त्रोत माना गया है। सात तारों के इस समूह को हमारे वैदिक ऋषियों ने गले का हार की संज्ञा दी है। कृतिका शब्द का अर्थ है कार्य सिद्ध करने वाली महिला, जिसमे कृत का अर्थ है क्रियान्वित या निर्मित। कृतिका नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी है, इसके अलावा भगवान कार्तिकेय के वाहन मोर को भी कृतिका नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी का लालन-पालन कृतिकाओं के द्वारा ही हुआ था। इस कारण इस नक्षत्र के अधिदेवता भगवान कार्तिकेय जी है। जो कि देवताओं के सेनापति हैं। ग्रह परिषद के राजा भगवान सूर्य को इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह माना जाता है।

स्वभाव : वराहमिहिर के अनुसार कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक काफी ऊर्जावान, साहसी, यशस्वी, पराक्रमी तथा न्यायप्रिय होते है। किसी भी क्रिया के परिणाम का विश्लेषण कर उनमें छिपे दोष को ढूंढ निकालने में काफी सक्षम होते है। इस नक्षत्र के जातक सौम्य, शिष्ट व मर्यादित आचरण करने वाले होते हैं। अपनी इच्छा शक्ति, स्वावलंबी स्वभाव व स्नेहपूर्ण सहयोग से लोगो को लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देते हैं।

कैरियर: कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक सफल व्यापारी, वकील, न्यायाधीश, शिक्षक, समीक्षक, अध्यक्ष, आपदा प्रबंधक अधिकारी, निशानेबाजी, आध्यात्मिक गुरु व उपदेशक, लुहार, सभी प्रकार के अग्नि संबंधित कार्य, मशीनरी आदि कार्यों में सफल होते हैं।

रोग: इस नक्षत्र के जातकों को दांतो व हड्डियों से संबंधित रोग, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, गैस्ट्रिक व पित्त संबधी समस्या होती है।

उपाय: कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए भगवान कार्तिकेय तथा हनुमान जी की उपासना काफी लाभकारी सिद्ध होती है। इसके अलावा गायत्री मंत्र जप तथा सूर्य स्तवन से अनिष्ट प्रभाव दूर करने में उपयोगी पाया गया है। इस नक्षत्र के जातकों के लिए लाल, पीले तथा केसरिया रंग के वस्त्र लाभकारी होते हैं।

वरद तिलकुंद चतुर्थी

माघ महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस माह का विशेष महत्व है और इस खास महीने में कई त्योहार पड़ते हैं इसी में वरद तिल चतुर्थी भी है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल कुंद चतुर्थी या वरद तिल चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। वरद तिल चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा तिल और कुंद के फूलों से किए जाने का विधान है। वरद तिल चतुर्थी 1 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। तिल और कुंद के फूल श्रीगणेश को अतिप्रिय है। कुछ लोग इस दिन गणेश जी को भोग के रूप में लड्डू भी अर्पित करते हैं।

वरद तिल चतुर्थी तिथि माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभः 01 फरवरी 2025, प्रातः11:38 से

माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्तः 02 फरवरी 2025, प्रातः 09:14 पर

वरद तिल चतुर्थी का पूजा मुहूर्त 01 फरवरी 2025, प्रातः 11:38 से दोपहर 01:40 तक

इस तरह वरद तिल चतुर्थी का व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। शास्त्र विहित मत मानें तो जिस दिन चतुर्थी तिथि लगी है चतुर्थी का व्रत भी उसी दिन से शुरू होगा।

वरद तिल चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा का महत्व माघ तिलकुंद चतुर्थी पर भगवान गणेश और चंद्र देव की पूजा से मन को शांति और सुख मिलता है। इस दिन व्रत रखने से गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और धन, विद्या, बुद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। रिद्धि-सिद्धि की भी प्राप्ति होती है और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं।

गणेश जी की पूजा से होती है हर मनोकामना पूरी संकष्टी चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का प्राकट्य दिवस माना जाता है। इसके बाद आने वाली वरद तिल कुंड चतुर्थी भी अपना विशेष महत्व रखती है। आगामी शुक्रवार को भगवान श्री गणेश की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। इस दिन पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होगी।

यह भी रहेगा विशेष माघ मास में शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि चल रही है। वर्तमान समय गुप्त नवरात्रि के साथ वरद तिल कुंड चतुर्थी का योग बनने से एक अद्भुत संयोग उत्पन्न हुआ है। इस दौरान गुप्त साधक श्री गणेश के मंत्रों के साथ-साथ आदि शक्ति के मंत्रों से संपुटिक अनुष्ठान करते हैं। अर्थात एक मंत्र भगवान श्री गणेश का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद एक मंत्र माता जी का पढ़ा जाता है। इस प्रकार संपूटिक अनुष्ठान संपन्न होता है।

वरद तिल चतुर्थी की पूजा विधि वरद तिल चतुर्थी गणेश जी की पूजा को समर्पित है।

वरद तिल चतुर्थी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त में की जाती है। वरद तिल चतुर्थी के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर साफ-स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद आसन पर बैठकर भगवान श्रीगणेश का पूजन करें।

पूजा के दौरान भगवान श्रीगणेश को धूप-दीप दिखाएं। अब श्री गणेश को फल, फूल, चावल, रौली, मौली चढ़ाएं।

पंचामृत से स्नान कराने के बाद तिल अथवा तिल-गुड़ से बनी वस्तुओं व लड्डुओं का भोग लगाएं। जब श्रीगणेश की पूजा करें तो अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। पूजा के बाद 'ॐ श्रीगणेशाय नमः' का जाप 108 बार करें।

शाम के समय कथा सुनें व भगवान की आरती उतारें।

शास्त्रों के अनुसार इस दिन गर्म कपड़े, कंबल, कपड़े व तिल आदि का दान करें।

सामाजिक नैतिकता को दीमक सरीखा चाट रहा एकल परिवारों का चलन

बढ़ते एकल परिवारों ने हमारे समाज का स्वरूप ही बदल दिया। आजकल के बच्चों को वो संस्कार और अनुशासन नहीं मिल रहे है जो उन्हें संयुक्त परिवारों से विरासत में मिलते थे, और इसी का परिणाम है कि समाज में परिवारों का टूटना, घरेलू हिंसा, असुरक्षा की भावना, आत्महत्या, बलात्कार, अपहरण आदि सामाजिक समस्याओं ने अपने पांव पसार लिए हैं। सबसे बड़ी चिंतनीय स्थिति तो हमारे बुजुर्गों की हो गई है। हालांकि बढ़ते एकल परिवारों का मूल कारण संयुक्त परिवारों की बंदिशें रूढ़ियां और परंपराएं ही है। अभी भी लोगों अपनी सोच को जमाने के हिसाब से ढालने की जरूरत है।

प्रियंका सौरभ

एकल परिवारों के बढ़ते प्रभाव ने, जिसमें माता-पिता और बच्चों के छोटे परिवार शामिल हैं, अपने स्वयं के परिवार के समूह को काफ़ी प्रेरित किया है, विशेष रूप से मूल्यों को विकसित करने में इसके पारंपरिक कार्य को। शहरीकरण, वित्तीय दबावों और व्यक्तिवादी जीवन शैली के माध्यम से प्रेरित इस बदलाव ने मूल्यों को हस्तांतरित करने के तरीके को बदल दिया है। जबकि एकल परिवार स्वतंत्रता और निजी विकास की अनुमति देते हैं, इसके अलावा उन्हें सांस्कृतिक, नैतिक और नैतिक मूल्यों को प्रसारित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो पहले विस्तारित स्वयं के परिवार के ढांचे के माध्यम से मज़बूत होते थे। मूल्यों को विकसित करने के लिए एक संस्था के रूप में परिवार पर प्रभाव मूल्य संचरण में विस्तारित परिवार की भूमिका कम हो गई है।

पारंपरिक संयुक्त परिवारों में, दादा-दादी, चाचा और चाची ने कहानी सुनाने, सलाह देने और बड़ों के लिए पहचान और नेटवर्क भावना जैसे सामूहिक मूल्यों को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकल परिवारों के साथ, यह अंतर-पीढ़ीगत सम्बंध कमजोर हो गया है, जिससे बच्चों के विभिन्न दृष्टिकोणों के संपर्क में आने पर रोक लग गई है। कन्फ्यूशियस ने सद्गुण की पहली क्षमता के रूप में अपने परिवार के सदस्यों पर ज़ोर दिया। बहु-पीढ़ीगत जीवन की गिरावट भी इस नैतिक शिक्षा को कमजोर कर सकती है। एकल परिवारों में, माता-पिता मूल्यों की आपूर्ति का पूरा बोझ उठाते हैं, नियमित रूप से पेशेवर प्रतिबद्धताओं के साथ इसे जोड़ते हैं। इससे समय की कमी या तनाव के कारण कमी आ सकती है। शहरी एकल परिवार सहानुभूति या धैर्य की कोचिंग पर शैक्षिक पूर्ति को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे बच्चों में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण पैदा होता है।

एकल परिवार स्वायत्तता, निर्णय लेने और व्यक्तिगत जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, जो वर्तमान सामाजिक मांगों के साथ संरेखित होते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक गुणों के रूप में महत्त्व दिया, जिसे एकल परिवार प्रभावी रूप से बेचते हैं। एकल परिवार अक्सर अपने परिवार की ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे निस्संदेह सामूहिक मूल्यों जैसे कि साझा करना, त्याग करना और आपसी सहायता के प्रति जागरूकता कम हो जाती है, जो संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए आवश्यक थे। त्यौहार, जो कभी संयुक्त परिवारों में नेटवर्क और सांस्कृतिक बंधन को मज़बूत करते थे, अब एकांत में मनाए जाने लगे हैं। जबकि पारंपरिक व्यवस्थाएँ कमजोर होती जा रही हैं, एकल परिवार शिक्षा के लिए स्कूलों, साथियों के समूहों और आभासी प्रणालियों पर अधिक से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं।

हालाँकि, निजी सलाह की कमी से नैतिक विकास में भी कमी आ सकती है। एकल परिवारों में, एक से अधिक पदों के मॉडल की अनुपस्थिति बच्चों की कई गुणों को देखने और उनका अध्ययन करने की क्षमता को भी सीमित कर सकती है। एकल परिवारों के बढ़ते ज़ोर ने मूल्यों को विकसित करने में परिवार की स्थिति को नया रूप दिया है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए, यह अक्सर विस्तारित परिवारों द्वारा प्रदान की गई सामूहिक जानकारी और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूकता को कम करता है। इस अंतर को पाटने के लिए, एकल परिवारों को सुखद पालन-पोषण, नेटवर्क कनेक्शन को बढ़ावा देने और जिम्मेदारी से आधुनिक उपकरणों का लाभ उठाने पर ज़ोर देते हुए सचेत रूप से अनुकूलन करना चाहिए। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा, ₹राज्य की ऊर्जा घर की अखंडता से प्राप्त होती है,₹ इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि परिवार, चाहे किसी भी संरचना में हों, नैतिक नागरिकों को आकार देने के लिए मूल्यवान बने रहते हैं।

एकल परिवार-परिवार प्राइमेट मानव समाज की एक ₹जैविक₹ घटना है। यह मानव विकास के विकासवादी संग्रह में एक अनुकूली रूप नहीं है और न ही आर्थिक समाज की एक उपयोगी चीज है। बल्कि यह मानव समय और सामाजिक स्थान में लगभग प्रथागत है। इसका केंद्रक पति-पत्नी और माता-पिता-बच्चों की एक इकाई है। इसका सामान्य रूप अक्सर मृत्यु या परित्याग या संतान की हानि के कारण ग़लत हो जाता है, लेकिन इसका मॉडल रूप अधिकतम स्थिर होता है। सभी परिस्थितियों में परिवार के भीतर पति या पत्नी के बुज़ुर्ग माता-पिता और कभी-कभी अतिरिक्त दूरस्थ परिवार होने की प्रवृत्ति होती है, हालांकि वे अर्ध-बाहरी कारक किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि आवश्यकता और पितृभक्ति से अधिक होते हैं। अलग-अलग सामाजिक परिस्थितियों में एकल परिवार ₹कुलों₹, जातियों, गांवों और सार्वजनिक विनियमन के माध्यम से विभिन्न तरीकों का उपयोग करके बाहरी समाज में एकजुट होते हैं।

पश्चिमी समाज में परमाणु इकाई नैतिक प्रबंधन के लिए आध्यात्मिक नौकरशाही और शासन उद्देश्यों के लिए नागरिक विनियमन के लिए अधिक से अधिक कठिनाई बन गई है। रिश्तेदारों ने, प्रियजनों के अलावा, शक्ति खो दी है। इसने अपने स्वयं के परिवार को अत्यधिक नैतिकता के अपने पूर्व राज्य की तुलना में अधिक ₹तथ्यात्मक₹ बना दिया है। परिणामस्वरूप परमाणु परिवार कमजोर हो गया है क्योंकि यह काफ़ी हद तक धर्म का संगठन है और अब मुकदमेबाजी और सार्वजनिक विनियमन की सहायता से बहुत अधिक नियंत्रणीय नहीं है। इसलिए यह पश्चिमी देशों में ठीक से नहीं चल रहा है, जिससे मौलिक प्राइमेट मूल्यों को आम तौर पर नुक़सान होता है। यह परिवार निगमों के सुधार की ओर ले जाता है जो ₹सहजऋ नैतिक दबावों को फिर से तस्वीर में लाते हैं। परमाणु परिवार के परिवार का भाग्य, जिसे यहाँ ₹प्रतिक्रांतिऋ कहा जाता है, संभवतः अगली पीढ़ी में रिश्तेदारों की सहायता से बढ़ती सहायता में से एक होगा।

सामाजिक ढांचे में इतना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि अब लिव इन रिलेशनशिप और वैवाहिक मामलों में थोड़ा बहुत ही अंतर रह गया होगा जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं और पुरुष वैवाहिक संबंधों में रुचि ना लेकर एकल रहने को वरीयता देने लगे हैं। गलती इसमें किसी भी परिजन कि ना होकर पश्चिमी मूल्यों को तरजीह दिए जाने की है। हम हिन्दुस्तानी अब ज़िम्मेदारियों को निभाने की तुलना में उस से अलग हो जाना बेहतर समझने लगे हैं।

अब पश्चिम में अपने ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों के छोटे अंतराल पर चक्रीय रूप से स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। 55, 000 परिवारों का एक अध्ययन इस सुझाए गए उलटफेर को दर्शाता है।

मौत के आंकड़ों में तब्दील होती भीड़ और बेखौफ हुकूमत

मन ना रँगाए, रँगाए जोगी कपड़ा
दाढ़ी बाढ़ाय जोगी होई गेलें बकरा

कबीर की ये पंक्तियाँ किसी एक युग की नहीं, बल्कि हर दौर की कड़वी सच्चाई को बयां करती हैं। धर्म और आस्था के नाम पर, भक्ति और विश्वास के नाम पर जो खेल सदियों से चलता आया है, वह आज भी बदस्तूर जारी है। आप मरते हैं, कुचले जाते हैं, भूख से तड़पते हैं, भगदड़ में दम तोड़ते हैं, लेकिन जिनके लिए आप अपनी जान की बाज़ी लगा देते हैं, वे सुरक्षित रहते हैं।

आशीष कुमार, स्पेशल रिपोर्टर परिवहन विशेष

आपकी लाशों को तितर-बितर कर दिया जाता है कि कहीं मौत के बाद भी आप सवाल ना उठवादो. कहीं एक जगह रखी लाशों से सच वैसा न दिखने लगे, जैसा है. कहीं आपकी वजह से किसी आला अधिकारी की नौकरी न चली जाए, कहीं आपकी वजह से किसी सफ़ेदपोश की कुर्सी न हिल जाए. आप आज पहली बार थोड़ी न मरे हो. आप तो रोज़ मरते हो. कभी किसी पुल में दब जाओगे, कभी किसी रेल हादसे में, कभी कुम्भ में पुण्य की प्रतीक्षा में मरोगे, कभी कोविड में नदी किनारे दफ़ना दिए जाओगे' और जब ज़िंदा रहते हो तो भूख से मरते हो, बेरोजगारी से मरते हो, महंगाई से मरते हो, शिक्षा की कमी से मरते हो। आप बस एक आंकड़ा हो.

उन्हें पता है कि आपकी कीमत 5 या 10 लाख का मुआवज़ा भर है. उन्हें ये भी पता है कि आपकी किसी को नहीं पड़ी, कोई नहीं जानना चाहता कि कोई हादसा कैसे हुआ, इसे रोकना किसकी ज़िम्मेदारी थी, मीडिया से लेकर प्रशासन और नेता तक हर हादसे के बाद अगर कुछ करते हैं तो बस विशुद्ध लीपापोती. 2 दिन बाद न तुम ये याद रखोगे न वो ये याद रखेंगे. इस ' आप ' में हम सब शामिल हैं Non- VIP' बाक़ी जो बड़े-बड़े इश्तहारों के बैनर और पोस्टर हैं, इन्हें कभी गौर से देखा है? अपनी पीठ थपथपाती सरकारें कभी नहीं छापेंगी कि मौत का आंकड़ा कितना था

आप कभी हाथरस में पैरों तले कुचल दिए जाते हैं, कभी कुंभ में रौंद दिए जाते हैं। कभी किसी पुल के ढहने से आपकी हड्डियाँ चकनाचूर हो जाती हैं, तो कभी किसी रेल हादसे में आपका शरीर पटरियों पर बिखर जाता है। मरने के बाद आपकी बस गिनती होती है, कभी 15, कभी 30, कभी 100, और जितनी बताई जाती है, उससे कहीं ज़्यादा छुपा ली जाती है। क्योंकि अगर असली आंकड़ा बाहर आ गया, तो सवाल उठेंगे, जवाब देने पड़ेंगे, और सत्ता को जवाब देने की आदत नहीं होती।

आपकी लाशों को जल्द से जल्द ठिकाने लगा दिया जाता है, ताकि मौत के बाद भी आप कोई सवाल न उठा सकें। कहीं ऐसा न हो कि आपकी मौत की बिखरी हुई तस्वीरें सत्ता की चमकती दीवारों पर दाग़ छोड़ दें। कहीं ऐसा न हो कि आपकी कराह सुनकर जनता जाग जाए। कहीं ऐसा न हो कि आपके परिजनों की चीखें किसी नेता की तकरीर में खलल डाल दें। सत्ता के गलियारों में आपकी मौत कोई त्रासदी नहीं, बल्कि एक "मैनेज करने वाली घटना" होती है। इसे जितनी जल्दी दफन कर दिया जाए, उतना ही बेहतर।

हाथरस भगदड़ में कौन जिम्मेदार था?

कथा सुनने गए मासूमों की लाशों का हिसाब किसने दिया?

क्या हुआ उस बाबा का, कितने लोग उस केस मैं सलाखों के पीछे है?

महाकुंभ में किसकी लापरवाही से मौतें हुईं? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है।

सरकार से कौन पूछेगा कि इतना बड़ा आयोजन था, फिर भी भीड़ नियंत्रण का इंतज़ाम क्यों नहीं था?

पर कोई नहीं पूछता, क्योंकि सरकार को पता है कि यह भीड़ धार्मिक जोश में मरने वाली भीड़ है, सवाल करने वाली भीड़ नहीं।

और जब सवाल नहीं होंगे, तो जवाब भी नहीं मिलेंगे।

देखिए, इस देश में धर्म के नाम पर मरना आसान है, लेकिन हक़ के लिए लड़ना गुनाह बन गया है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लाठियां खाते हैं, पर धर्म की भीड़ में मारे जाने वाले मुआवज़े से संतुष्ट हो जाते हैं।

आपकी जान सिर्फ एक आंकड़ा है

क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, तो तुरंत आंकड़ों का खेल शुरू हो जाता है? प्रशासन कहता है, ₹अब तक 25 लोगों की मौत हुई है।₹ मीडिया कहता है, ₹सूत्रों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 50 से ज़्यादा हो सकती है।₹ प्रत्यक्षदर्शी चिल्लाते हैं, ₹हमने खुद 100 से ज़्यादा लाशें देखी हैं।₹ और सरकार? सरकार बस लीपापोती करने में जुट जाती है।

सरकारी रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या हमेशा कम ही बताई जाती है। क्योंकि अगर असली संख्या सामने आ गई, तो जिम्मेदारियों की पड़ताल शुरू हो जाएगी, कुर्सियाँ हिलने लगेंगी, अफसरों की फाइलें खुलने लगेंगी, और नेताओं के भाषणों की चमक फीकी पड़ जाएगी। इसीलिए, मौतों को छिपाने की पूरी कोशिश की जाती है।

लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर किसकी मौत मायने रखती है? अगर कोई बड़ा उद्योगपति मरता है, तो सरकार मुआवज़े के साथ संवेदना भी व्यक्त करती है। अगर किसी नेता के परिवार का कोई व्यक्ति किसी सड़क दुर्घटना में मारा जाता है, तो पूरा सरकारी तंत्र सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब कोई आम आदमी किसी भगदड़ में कुचलकर दम तोड़ देता है, तो उसकी मौत को बस एक संख्या में समेट दिया जाता है।

कौन लेगा जिम्मेदारी?

कुंभ में भगदड़ होती है, सैकड़ों मरते हैं। नेता कहते हैं, ₹ऐसे आयोजनों में छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती हैं।₹ हाथरस में भीड़ बेकाबू हो जाती है, लोगों की साँसे बंद हो जाती हैं, लेकिन सरकार कहती है, ₹इसे तूल मत दीजिए, मामला संवेदनशील है।₹ सवाल यह है कि इन मौतों की जवाबदेही कौन लेगा?

क्या किसी बड़े अधिकारी को इस लापरवाही के लिए जेल हुई? नहीं! जो लोग इन मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे हमेशा बच निकलते हैं।

वीआईपी और आम जनता में फर्क क्यों?

आपने कभी सुना कि किसी मंत्री का बेटा किसी भगदड़ में मारा गया हो? कभी कोई उद्योगपति ट्रेन हादसे में मरा हो? नहीं। क्योंकि उनके लिए खास सुविधाएँ होती हैं। उनके लिए भीड़ नहीं होती, ट्रैफिक नहीं होता, मेडिकल इमरजेंसी की कोई दिक्कत नहीं होती। वे कहीं भी जाएं, सुरक्षा घेरे में चलते हैं, लेकिन आपको किसी की भीड़ में धकेल दिया जाता है।

इस देश में वीआईपी कल्चर इतना हावी हो चुका है कि आम आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं रही। सत्ता के गलियारों में बैठने वालों के लिए जनता सिर्फ एक वोट बैंक है। जब वोट चाहिए, तब आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बारी आती है, तो सरकार कहती है, ₹हम क्या कर सकते हैं? यह तो कुदरती आपदा थी!₹ 'भगवान ने बुलाया है!

धर्म के नाम पर बलिदान सिर्फ गरीब देगा?

धर्म को हथियार बनाकर जिन लोगों को मरने के लिए उकसाया जाता है, क्या उनमें कभी कोई मंत्री, नेता या उद्योगपति शामिल होता है? उनके बेटे-बेटियाँ कभी किसी भगदड़ में क्यों नहीं मारे जाते? क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वहाँ उनका भविष्य सुरक्षित रहता है। लेकिन आपके बच्चे? वे धर्म के नाम पर मरते हैं, बलिदान देते हैं, और अंत में सिर्फ आंकड़ों में सिमटकर रह जाते हैं।

धर्म में विश्वास रखना गलत नहीं है, लेकिन अंधभक्ति करना कहाँ तक सही है? आज धार्मिक आयोजन, जो कभी आध्यात्मिक शांति के लिए होते थे, अब भीड़तंत्र और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन चुके हैं। भक्तों के लिए वहाँ सिर्फ धक्के, भगदड़ और मौतें हैं, जबकि बड़े बाबा और नेता वीआईपी काफिलों में आते हैं, विशेष सुविधाओं के साथ दर्शन करते हैं, और लौट जाते हैं।

"किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है!"

राहत इंदौरी ने सही कहा था—

"किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है!"

यह देश किसी एक विचारधारा, किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी एक तबके की जागीर नहीं है। यह देश संविधान से चलेगा, धर्म के ठेकेदारों से नहीं। यह देश लोकतंत्र की बुनियाद पर टिका है, किसी एक पार्टी या विचारधारा के हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कोई सवाल नहीं पूछ सकता।

अगर आप सवाल उठाएँ, तो आपको देशद्रोही करार दिया जाता है। बाबा आ कर बोलते है कि अगर आप महाकुंभ नहीं आते है तो आप देशद्रोही है.. क्या हो गया है.. कैसा देश बनाना चाह रहे है हम.. कौन होते है ये किसी को सर्टिफिकेट बांटने वाले की कौन देशद्रोही है कौन देशभक्त है। प्रशाशन क्या कर रही है.. क्या करवाई हुई इस बयान पर.. यह देश बुद्ध की है ये गांधी आंबेडकर नेहरू का देश है.. ये देश संविधान से चलेगा.. अगर आप पूछें कि इतनी मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो आपको चुप कराया जाता है। लेकिन यह सवाल पूछना ज़रूरी है। यह जानना ज़रूरी है कि आपकी मौत सिर्फ एक आंकड़ा क्यों बनती जा रही है?

आप कब तक चुप रहेंगे?

आप दो दिन तक आक्रोशित रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप फिर उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, फिर उसी नेता की रैली में नारे लगाते हैं, फिर उसी धार्मिक आयोजन में धक्के खाते हैं, फिर उसी प्रशासन से उम्मीदें लगाते हैं। आप फिर से मरने के लिए तैयार हो जाते हैं।

यह चक्र तभी रुकेगा जब आप खुद अपनी आवाज़ उठाएँगे। जब आप सत्ता से सवाल पूछेंगे, जब आप अपने हक़ की माँग करेंगे। जब आप यह कहेंगे कि

"हम सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं हैं, हमारी जान की भी कीमत है!"

क्योंकि अगर आप नहीं बोले, तो अगली भगदड़ में, अगली दुर्घटना में, अगली महामारी में मरने वालों की सूची में अगला नाम आपका भी हो सकता है।

कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुला समर्थन: दिल्ली देहात मोर्चा

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली देहात मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली देहात के किसानों ने कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को सम्मानित करते हुए पगड़ी बांधी और शाल भेंट किया। इस अवसर पर किसानों ने कांग्रेस पार्टी को अपना खुला समर्थन देने की घोषणा की और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील की। विभिन्न गांवों से आए किसानों ने प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में दिल्ली देहात के सभी लंबित मुद्दों को शामिल करना एक ऐतिहासिक कदम है, जो दिल्ली देहात को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिल्ली देहात के विकास के लिए कई प्रमुख बिंदु शामिल किए गए हैं, जिनमें ₹सबको प्लॉट, स्मार्ट गांव₹ योजना को लागू करना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आवंटित 74/4 जमीन वाले किसानों को मालिकाना हक प्रदान करना, कृषि भूमि के सर्किल रेट को 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ करना और लैंड पूलिंग पॉलिसी की व्यावहारिक समीक्षा करना शामिल है।

इसके अलावा, दिल्ली देहात के युवाओं को उच्च शिक्षा का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए नजफगढ़ में वेस्ट कैंपस और बवाना में नॉर्थ वेस्ट कैंपस खोलने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है।

जय किसान आंदोलन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक, किसान नेता राजीव यादव ने कहा कि दिल्ली की वर्तमान सरकार ने देहात क्षेत्र को 20 साल पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच लगातार खींचतान के कारण कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। ऐसे में, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर दिल्ली देहात के समावेशी विकास को गति देना आवश्यक हो गया है।

इस कार्यक्रम में किसानों के प्रतिनिधिमंडल में ढासा 12 खाप के SC समाज के पूर्व प्रधान चौखराज कटारिया, चौधरी दिलबाग सिंह नीलवाल, डॉक्टर रामनिवास यादव (सुरेहड़ा), जगदीश यादव (कांगन हेड़ी), नरेंद्र यादव (घुम्मनहेड़ा), रोहताश सिंह राणा (घेवरा), ब्रिजेंद्र सिंह यादव (दौलतपुर), करण सिंह (बापडोला), देवेंद्र कुमार डागर (समसपुर खालसा) सहित कई वरिष्ठ किसान नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

लक्ष्मीनगर सें बसपा प्रत्याशी वकार चौधरी को मिला मुस्लिम उलेमा का समर्थन

सुषमा रानी

नई दिल्ली। लक्ष्मी नगर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी वकार चौधरी को मुस्लिम उलेमा का पूरा समर्थन मिल गया है। इस सिलसिले में एक खास बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के मौलवियों और मुस्लिम समुदाय के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। बैठक में उलेमाओं ने एकजुट होकर वकार चौधरी के पक्ष में मतदान की अपील की। इसके बाद मस्जिदों के बाहर भी प्रचार किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बसपा के समर्थन में आएं। बैठक में मरकज़ और मौलाना साद पर दर्ज एफ आई आर का मुद्दा भी उठा। मुस्लिम नेताओं ने इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताया और कहा कि वे इस चुनाव में अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इस समर्थन से वकार चौधरी की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। उन्होंने उलेमाओं और समुदाय का आभार जताते हुए कहा कि वे सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि यह समर्थन चुनावी नतीजों में कितना असर डालता है।

पूर्व सैनिकों के हितों के संरक्षण हेतू पूर्व सैनिक आयोग का गठन करेंगे : हरीश रावत

सुषमा रानी

नई दिल्ली। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषणा पत्र में वायु, जल और भूमि प्रदूषण से मुक्ति सहित पूर्व सैनिकों हेतु योजनाओं के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया।

संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभय दूबे, कम्युनिकेशन विभाग के ज्योति सिंह, रश्मि सिंह मिगलानी, आस्मा तस्लीम और डा0 अरुण अग्रवाल भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी के लिए संघर्ष कर रहे है। पिछले 11 वर्षों में भाजपा और आम आदमी पार्टी की खींचतान के कारण दिल्ली में हवा सांस लेने लायक नही रही और पानी हाथ लगाने के लायक नही, नहाना और पीना तो दूर की बात है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भाजपा शासित शहरों सहित दिल्ली में पिछले एक दशक में ग्रीन कवर घटा है, दिल्ली में ग्रीन कवर 35 प्रतिशत घटा है। दिल्ली में स्थिति इतनी खराब है, यहां हवा में जहर है और यमुना प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप करने अपनी जिम्मेदारियों को भाग रहे है। यमुना सफाई पर 8500 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी दिल्ली में पीने का पानी नही मिल रहा है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी और भाजपा जिम्मेदार है। कांग्रेस दिल्ली के बड़े नालों और कॉलोनियों से निकलने वाली गंदे पानी को ट्रीट करके आगे यमुना में डालेगी और नजफगढ़, शाहदरा इत्यादि बड़े नालों को ढकने का काम करेगी, जिसके लिए नीति निर्धारण किया जाऐगा। 2041 मास्टर प्लान के अनुसार विभिन्न कॉलोनियों में पार्क विकसित करेंगे।

हरीश रावत ने दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सरकार बनने पर बेहतर बनाएंगे।

1. 2016 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाए गए थे, 8 साल से उनका पालन नहीं किया गया।

2. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की धारा 5 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इन नियमों के अनुपालन की मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व सौंपा गया है तथा एक केंद्रीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य के मंत्रालयों सहित 11 सदस्य और 2 विशेषज्ञों को रखा गया है और इन सभी के अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए।

3. धारा 15 में इस बात को निर्धारित किया गया था कि इन नियमों के अधिसूचित होने के छः माह में राज्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नीति और रणनीति के अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रबंधन योजना तैयार करेगा।

4. इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर उपविधियाँ बना कर समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

5. दिल्ली में 3 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीएम

6. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने 19/09/2024 को अपनी एन्युअल रिपोर्ट में इस बात का खुद खुलासा किया है कि दिल्ली में 11,342 टन प्रतिदिन सोलिड वेस्ट निकलता है, जिसमें से 7,542 टन प्रतिदिन सोलिड वेस्ट ट्रीट किया जाता है और 3,800 टन प्रतिदिन सोलिड

वेस्ट 35 प्रतिशत वर्तमान में तीन लैंडफ़लि साईट भलस्वा, गाज़ीपुर और ओखला में डम्प किया जाता है।

7. एमसीडी से 11000 टन प्रतिदिन सॉलिड वेस्ट निकलता है

8. एनडीएमसी से 280 टन प्रतिदिन सॉलिड वेस्ट निकलता है।

9. डीसीबी से 62 टन प्रतिदिन सॉलिड वेस्ट निकलता है।

10. 19/12/24 को जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल' 2016 के नॉन-कंप्लायंस के संदर्भ में आदेश पारित करते हुए कहा कि आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) 11,000 टन सॉलिड वेस्ट प्रतिदिन निकलता है, जिसमें से 3,000 टन प्रोसेस ही नहीं किया जाता है, अनट्रीटेड रह जाता है, जो बहुत ही चौंकाने वाला है। दुख की बात यह है कि यह बात हम राजधानी के लिए कह रहे हैं। अगर 3,000 टन सॉलिड वेस्ट ट्रीट नहीं किया जाता है, तो इसका अर्थ है कि इसकी बड़े पैमाने पर गैर कानूनी डंपिंग हो रही है।

11. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 344 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से सिर्फ 111 लोग ही काम कर रहे हैं, 233 पद खाली हैं। दिसंबर, 2024 में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सीक्यूएम द्वारा सबमिट रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि दिल्ली नगर निगम में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रतिदिन 11,000 टन उत्पादित हो रहा है, और सिर्फ 8,000 टन के लिए वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। अर्थात, 3,000 टन प्रतिदिन मुनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेस ही नहीं किया जा रहा है, जो कि सीधा-सीधा पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है।

12. कोर्ट ने हिदायत दी कि भारत सरकार तुरंत उन सक्षम प्राधिकारियों की मीटिंग बुलाए, जो 2016 के रूल को लागू कराने के लिए जिम्मेदार हैं। शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो 2016 के नियमों का पालन कराए, इसलिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित करते हुए एक कॉमप्रेहेंसिव कंप्लायंस रिपोर्ट 2016 के नियमों के तहत प्रस्तुत करे।

13. इसी के साथ, न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सरकार के शपथ पत्र से यह भी ज्ञात होता है कि 3,800 टन का सॉलिड वेस्ट प्रतिदिन गाज़ीपुर भलसवा में डंप किया जा रहा है। इन साईट्स पर आग लगने से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और इन साईट्स पर आग को रोका जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त सभी संदर्भों में सरकार 27 जनवरी, 2025 तक एक शपथपत्र दे और गाज़ीपुर और भलसवा डंपिंग साईट्स के लिए दिल्ली सरकार या एमसीडी या दोनों 15 जनवरी 2025 तक एक डिटेल्ड एफिडेविट फाईल करे, और न्यायालय ने इसकी अगली सुनवाई 27 जनवरी निर्धारित की है।

रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने पर सैनिकों की शिकायतों को हल करने के लिए दिल्ली में एक पूर्व सैनिक आयोग का गठन करेंगे। अग्निवीर योजना को वापस लेने और अग्नि वीरों को स्थायी करने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाऐंगे। पूर्व सैनिकों के लिए दिल्ली सरकार और संबधित निकायों में पद आरक्षित करके पदों पर पूर्व सैनिकों की भर्ती होगी। कांग्रेस सरकार में आने पर दिल्ली के शहीद सैनिकों ;रक्षा एवं अर्धसैनिक बलद्ध की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ करेंगे और रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों के एक आश्रित या परिवार के सदस्य को दिल्ली सरकार में नौकरी देंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस 8 फरवरी को सरकार बनाने के बाद महिला कल्याण बोर्ड का गठन करेगी जो लाडली योजना की तरह ही महिलाओं और बच्चियों को उत्थान और संरक्षण के लिए काम करेगा। दिल्ली में गरीबों के लिए 100 इंदिरा कैंटीन खोली जाऐगी जिसका संचालन महिलाओं के हाथों में सौंपा जाएगा। कांग्रेस दिल्ली को आगनबाड़ी और आशा वकर्स को सर्वोच्च मानदेय देने वाला राज्य बनाऐगी और इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे।

शरजील इमाम और अभिषेक मनु सिंघवी बिना फिल्म देखे परेशान है : देवेंद्र मालवीय निर्देशक "2020 दिल्ली"

सुषमा रानी

नई दिल्ली के प्लाजा पीवीआर में आज अपनी रिलीज से पहले ही जबरदस्त विवादों में घिर चुकी फिल्म 2020 दिल्ली को प्रमोट करने फिल्म के निर्माता देवेंद्र मालवीय और फिल्म के प्रमुख कलाकार मीडिया से बात कर ही रहे थे कि इसी बीच उन्हें उनके साथ आए एडवोकेट ने खबर दी कि दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने फिल्म की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। इस खबर पर निर्माता निर्देशक देवेंद्र मालवीय ने कहा कि पता नहीं क्यों बिना फिल्म देख शरजील इमाम और अभिषेक मनु सिंघवी परेशान है।

बुलंद इरादों और अपने बढ़ाए कदम से जरा भी विचलित ना होते हुए देवेंद्र ने कहा हमे अभी कोर्ट से कोई सूचना नहीं मिली है हम कानून का सम्मान करते है और कानून के दायरे में रहते हुए तय करेंगे कि फिल्म अपनी पहले से तय तारीख पर ही रिलीज हो सके।

इस प्रेस वार्ता में निर्माता देवेंद्र के साथ आए अनुभवी फिल्म और टीवी एक्टर समर जयसिंह भी आए। देश की पहली सिंगल शॉट फिल्म में काम करने के अनुभव को मीडिया से शेयर किया।

समर कहते है इस फिल्म में काम करने का अनुभव मेरे लिए ही नहीं सभी कलाकारों के लिए बिल्कुल नया था सिंगल शॉट तकनीक में एक्टर को रिटेक का मौका नहीं मिलता सो मैने ही नहीं इस फिल्म के सभी कलाकारों ने बेहद मेहनत की , समर कहते है मुझे हैरानी होती है इस फिल्म को अभी किसी ने भी नहीं देखा 24 जनवरी को फिल्म का सिर्फ 3 मिनिट का ट्रेलर जारी किया और इसे देखते ही देश के नामी एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने फिल्म के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया उनका बयान देखिए कि वो हमारी इस फिल्म को देश की एकता और अखंडता के सबसे बड़ा खतरा बता रहे है। इन लोगों को नहीं मालूम कि फिल्म बनाने में मेकर और एक्टर से लेकर यूनिट के अनेक लोगों की कितनी मेहनत होती है ये लोग ऐसी सच को उजागर करने वाली फिल्म के मेकर का उत्साह बढ़ाने की बजाय उनका हौसला खत्म करने में लग जाते है ।

समर जयसिंह कहते है अभी हम लोगों को पता लगा कि दिल्ली हाइकोर्ट में दिल्ली दंगों के एक आरोपी ने फिल्म की रिलीज रोकने के लिए याचिका दायर कर दी है , यह फिल्म के मेकर और हम सबके लिए दुखद है , समर कहते है सच की हमेशा जीत होती है सो हमारी भी होगी और फिल्म दर्शको के सम्मुख होगी ।

निर्माता निर्देशक देवेंद्र मालवीय कहते है मैने करीब चार साल तक इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की बिना किसी बाहरी मदद अपनी फैमिली के सहयोग से बेहद महंगे प्रोजेक्ट को पूरा किया, अब जब हम फिल्म रिलीज करने की प्लानिंग में लगे है तो कुछ ऐसी ताकते भी है जो इस फिल्म को रोकने में लग गई है वो लोग नहीं चाहते कि 24 फरवरी 2020 के उस दिन का वह काला सच जब दिल्ली दंगों की आग ने झुलसी हुई थी 53 बेकसूर नागरिको की जान इन दंगों के भेंट चढ़ गई और यह सब उस वक्त हो रहा था जब अमेरिका के प्रेसीडेंट आए हुए थे ।

अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए देवेंद्र . मालवीय कहते है "इतने खौफनाक दिल दहला देने वाले दंगों और आगजनी की घटनाओं को जिस तरह से हमने सिंगल शॉट तकनीक में शूट किया वह हम सबके लिए जबरदस्त चुनौती रहा , मेरी यह फ़िल्म इस बात का सबूत है कि अगर आप अपना टारगेट हासिल करने चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता ,इस फिल्म में हमने अपने पड़ोसी देशों पाक और बांग्ला देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की दुर्दशा और देश में रह रहे विस्थापित हिंदुओं की दुर्दशा को पेश किया है , हमने पूरी रिसर्च के बाद फिल्म में दिखाया कि इन देशों में हिंदू लड़कियों के साथ रेप , और धर्मांतरण की घटनाएं होती है।

बता दे, इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक संगीतकार देवेंद्र मालवीय ने अपना फिल्मी सफर मुंबई में एक अभिनेता के रूप में शुरू हुआ कुछ अरसे बाद उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्टी में अपनी अलग पहचान बनाने का फैसला किया और इस प्रोजेक्ट में लग गए ।

जल्दी ही सिनेमा के पर्दे पर आ रही दिल्ली 2020 फिल्म में जाने माने एक्टर ब्रिजेंद्र काला, समर जय सिंह, सिद्धार्थ भारद्वाज, भूपेश सिंह, चेतन शर्मा और आकाश अरोरा जैसे कई मुझे हुए युवा और अनुभवी कलाकार नजर आएंगे।

नई दिल्ली विधानसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीतकर केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं- इमरान हुसैन

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली विधान सभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत को और पक्का करने के लिए बल्लीमारान से विधायक व दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने अरविन्द केजरीवाल के समर्थन में नई दिल्ली विधानसभा में जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों का उत्साह और अरविन्द केजरीवाल के प्रति प्रेम देखने लायक था सब लोगों ने झाड़ू के निशान पर बटन दबाने का संकल्प लिया। लोगों ने एक मत से ईमानदारी और विकास करने वाली सरकार फिर लाने का वादा किया। अरविन्द केजरीवाल के लिए लोगों का प्यार बता रहा है कि एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनने जा रहे हैं।

इसके साथ ही इमरान हुसैन ने जनसंपर्क के दौरान बल्लीमारान विधानसभा के अहाता काले साहब, विधानसभा के चिमनी मिल, पंजाबी फाटक में कॉर्नर मीटिंग और नुक्कड़ सभा करके लोगों का जनसमर्थन और आशीर्वाद माँगा। विधायक इमरान हुसैन ने प्रेमनगर में जनसभा को भी संबोधित किया और आम आदमी पार्टी को समर्थन की अपील की। बल्लीमारान के विधायक इमरान हुसैन लगातार विधानसभा के अलग-अलग इलाकों में जनसंपर्क कर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। विधायक इमरान हुसैन बल्लीमारान के जिस क्षेत्र से भी गुजरते हैं उनके साथ लगातार लोगों का हुजूम जुड़ता चला जाता है।

जनसंपर्क के दौरान इमरान हुसैन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बचत पत्र कैंपेन की शुरुआत की है। दिल्ली के लोग सरकारी योजनाओं से हर महीने अपने 25 हजार रुपये तक की बचत कर रहे हैं और नई योजनाओं के जरिए 10 हजार रुपये का अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा। इमरान हुसैन ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल बिजली, पानी, मुफ्त बस सेवा, शिक्षा और मोहल्ला क्लीनिक के जरिए जनता को ये बचत दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को लोकहित में चौथी बार अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। पद यात्रा के दौरान बल्लीमारान की गली- मोहल्ले में लोग विधायक इमरान हुसैन का तहे दिल से स्वागत करते हैं और केजरीवाल सरकार द्वारा किये गए विकास कार्यों के लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं ! इलाके की महिलाओं का मानना है कि केजरीवाल सरकार ने लड़कियों की शिक्षा पर बहुत सराहनीय काम किया है और बल्लीमारान के सरकारी स्कूलों मे शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है ।गली-मुहल्लों में स्ट्रीट लाइट लगने से इलाके से सभी स्थानों पर रोशनी के भी प्रयाप्त इंतजाम हो गए हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान इमरान हुसैन ने फिर से कहा कि विपक्षी पार्टी के लोग सिर्फ हवा-हवाई बातें करते है पर अरविन्द केजरीवाल जी आम आदमी के विकास की राजनीती करते हैं। इमरान हुसैन ने कहा कि कि अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र में नये स्कूल, स्कूल की नयी बिल्डिंग, हाई मास्ट लाइट, स्ट्रीट लाइट, कटरा में विकास कार्य, पानी के बोरिंग का काम, बिजली के तारों को सुव्यवस्थित व अंडरग्राउंड करने, सड़क-गलियों निर्माण एवं मरम्मत, पानी की नई पाइपलाइन ,सीवर लाइन कार्य, बरात घर, कम्युनिटी सेंटर एवं चौपाल निर्माण आदि विकास कार्य किये गए हैं। जनसंपर्क के दौरान इमरान हुसैन ने लोगों को बताया कि दिल्ली जनता के लिए केजरीवाल जी ने 15 गारंटियां दी हैं। अरविन्द केजरीवाल ने युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों से लेकर सभी वर्गों को ध्यान में रखकर इन गारंटियां पर मुहर लगाई है ।

भलस्वा में कूड़े के पहाड़ खत्म करुँगा, स्वच्छ पेयजल, 24 घंटे बिजली, बेरोजगारों युवकों की नौकरियां कांग्रेस देगी- देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि वह दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों में अमानवीय परिस्थितियों में बादली विधानसभा के लोग रहने को मजबूर है जिन्होंने केजरीवाल सरकार द्वारा किया कोई विकास क्षेत्र में नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि गंदा पीने का पानी, कचरा के ढेर, अत्यधिक जहरीली हवा और जल व भूमि प्रदूषण लोगों के जीवन का अभिशाप बन गए है।

बादली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेन्द्र यादव ने कहा कि विधायक रहते हुए उन्होंने बादली में बहुत सारे विकास कार्य किए थे और जब वे विधायक नहीं है तब भी निर्वाचन क्षेत्र की निगरानी और लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बादली क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की और केजरीवाल की विफलता ने भलस्वा में लैंडफिल और बड़ा पर्वत बन रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन के लिए गंभीर खतरा अन रहा है। निगम चुनावों में केजरीवाल ने दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को एक साल में खत्म करने का वादा किया था।

देवेन्द्र यादव का आज शुक्रवार को बादली में चुनाव अभियान अति व्यस्त रहा। उन्होंने दोपहर 12 बजे मेसरवाली कॉलोनी में जनसभा को सम्बोधित किया, 1 बजे मस्जिद के पास बादली में, 2 बजे बाल्मीकि मौहल्ला बादली में और 2.30 बजे भलस्वा की हरिजन कॉलोनी में जनसभा को संबोधित किया। 3-5 बजे तक आईटीआई, के-2 ब्लॉक जहांगीर पुरी में पदयात्रा निकाली, 5.30 बजे ई ब्लॉक यादव नगर में, सायं 6 बजे ई ब्लाक लांडी वाली गली और 6.30 बजे शिवपुरी टीचर कॉलोनी में भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली।

यादव ने कहा कि कांग्रेस अपनी सभी

पांच प्रमुख गारंटियों को जनता तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे नेता राहुल गांधी के विश्वास और आश्वासन व भरोसा हमें दिया दिया है प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देंगे, जीवन रक्षक योजना के तहत हर दिल्लीवासी को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा करके उनको स्वास्थ्य का अधिकार देंगे। बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में शिक्षित युवा बेरोजगार को एक वर्ष तक 8500 रुपये मासिक अप्रेंटसशिप देकर उनको प्राईवेट कम्पनियों में अवसर देंगे। बढ़ती मंहगाई को देखते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रसोई का बजट नियंत्रित करने के लिए 500 रुपये में सिलेंडर और राशन किट जिसमें 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो खाने का तेल, 6 किलो दाल और 250 ग्राम चाय पत्ती मुफ्त देंगे। पांचवी गारंटी हमारी में हम दिल्ली बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे।

पूर्वांचल, उत्तरांचल, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, जैन, सिक्खों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों सहित हर जाति, वर्ग और समुदाय के लोगों के लिए कांग्रेस घोषणापत्र में घोषित कई विभिन्न योजनाओं को बादली में रहने वालों को उपलब्ध कराया जाएगा। बादली एक मिनी भारत के रुप में जाना जाता है क्योंकि हर राज्य, वर्ग, जाति और समुदाय के लोग रहते है।

उन्होंने कहा कि 17 मार्च, 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मेयर शैली ऑबराय के साथ भलस्वा लैंडफिल का दौरा करके वादा किया था कि मार्च 2024 तक लैंडफिल खत्म कर देंगे। निगम चुनाव को 2 वर्ष से अधिक समय हो चुके है भलस्वा में कूड़े कम होने की जगह और बढ़ रहे है, 3 दिन पहले पहाड़ से कूड़ा गिरने के कारण 2 बच्चे घायल हो गए थे और कई घर दब गए थे। खबर देने के बावजूद स्थानीय विधायक घटनास्थल से गायब थे। भलस्वा लैंडफिल का पहाड़ लोगों के जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। मैंने वहां पहुँचकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ खुद को प्रभावित लोगों की मदद की और खतरे वाले घरों को खाली करके उनके रहने खाने का प्रबंध कराया था।

यादव ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र ने लैंडफिल को खत्म करने के लिए विशिष्ट योजनाओं को रेखांकित किया है। कांग्रेस सत्ता में आने पर पीने के पानी की आपूर्ति और 24 घंटे बिजली, गरीब झुग्गी वालों को मकान, सार्वजनिक टॉयलेट को स्वच्छ करने सहित बदहाली झेल रही बादली की जनता को बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए प्राथमिकता के तौर पर काम करेंगे।

महाकुंभ जाने वालों के लिए अच्छी खबर, NCR के इस इलाके से मिलेगी सीधी बस; सिर्फ इतना होगा किराया

महाकुंभ बस टिकट प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। गुरुग्राम से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा शनिवार से शुरू हो रही है। बस संचालन को लेकर रूट और किराया भी तय कर दिया गया है। गुरुग्राम से प्रयागराज का एक तरफ का किराया 955 रुपये निर्धारित किया गया है। लेख में पढ़िए पूरी खबर।

गुरुग्राम। प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। गुरुग्राम से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा शनिवार से शुरू हो जाएगी।

इससे जिले के लोग सीधा रोडवेज बस से महाकुंभ मेले में जा सकेंगे। बस संचालन को लेकर रूट और किराया भी तय कर दिया गया है। जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगी, वैसे-वैसे बसों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।

हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के महाप्रबंधक प्रदीप अहलावत का कहना है कि एक फरवरी से यह सेवा शुरू की जा रही है। प्रतिदिन गुरुग्राम बस अड्डे से साधारण श्रेणी की बस रोजाना शाम छह बजे प्रयागराज के लिए रवाना होगी व अगले दिन सुबह पांच बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

संगम में डुबकी लगाकर इसी बस से वापस लौटने की व्यवस्था

वापसी में यह बस निर्धारित पार्किंग स्थल से पुनः शाम छह बजे गुरुग्राम के लिए रवाना होगी। इससे श्रद्धालु आराम से संगम में डुबकी लगाकर इसी बस से वापस भी लौट सकते हैं।

गुरुग्राम से प्रयागराज का एक तरफ का किराया 955 रुपये निर्धारित किया गया है। बस यात्रा के लिए बस अड्डे पर स्थित ट्रैफिक शाखा में आफलाइन मोड यानी फिजिकल मोड में बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यात्रियों की संख्या के हिसाब से बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रतिदिन काफी संख्या में लोग गुरुग्राम से पहुंच रहे हैं:। ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है। फ्लाइट में भी जगह नहीं मिल रही है। इसे देखते हुए बस सेवा भी शुरू की गई है ताकि लोगों को पहुंचने में परेशानी न हो।

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 116 केंद्रों पर लग रहे शिविर

हर घर-हर गृहिणी योजना की समीक्षा अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा ने बुधवार को अपने कार्यालय में की। उन्होंने योजना की पात्रता व पंजीकरण के लिए अपनाए जा रहे मापदंडों की जानकारी ली। बैठक में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सौरभ कुमार ने बताया कि कुल 116 डिपो होल्डर स्तर पर पंजीकरण शिविर लगाने की व्यवस्था की गई है।

योजना अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाइ) व गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) राशन कार्ड धारक महिलाएं योजना में पंजीकरण के लिए पात्र हैं। योजना के तहत पंजीकृत परिवार की महिला मुखिया को मात्र 500 रुपये के भुगतान पर एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा।

सिलेंडर की अतिरिक्त कीमत पर सरकार की ओर से सब्सिडी के जरिए भुगतान किया जाएगा। पंजीकरण के लिए आवश्यक है कि पात्र महिला शिविर में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अलावा इसके साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर की जानकारी व बैंक खाता पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए। डीएम सीएससी विकास पूनिया ने बताया कि जिले के कुल 116 सीएससी सहायक इन पंजीकरण शिविर में नियुक्त किए गए हैं।

इंटरनेशनल फिल्म सिटी का लेआउट प्लान मंजूर, 1500 करोड़ का होगा निवेश; पढ़ें पूरी डिटेल

यमुना प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-21 में बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी के लेआउट प्लान को मंजूरी दे दी है। पहले फेज में 230 एकड़ में से 75 एकड़ में कमर्शियल डेवलपमेंट और 155 एकड़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा।

ग्रेटर नोएडा। यमुना अथारिटी ने यीडा सिटी के सेक्टर-21 के अंतर्गत इंटरनेशनल फिल्म सिटी का लेआउट प्लान बृहस्पतिवार को मंजूर कर दिया। 230 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी के पहले फेज में 75 एकड़ में कमर्शियल डेवलपमेंट का अप्रूवल दिया गया है, जबकि 155 एकड़ एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मंजूरी दी गई है।

230 एकड़ जमीन सात जोन में विकसित होगी। इसमें तीन जोन कमर्शियल डेवलपमेंट के होंगे, जबकि 4 जोन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रहेंगे। यीडा के सेक्टर-21 में 1,000 एकड़ में इंटरनेशनल फिल्म सिटी बननी है। पहले फेज के लिए 230 एकड़ के लेआउट प्लान को मंजूरी दी गई है। बाकी के दो फेज के लिए बाद में ग्लोबल टेंडर निकाले जाएंगे।

लेआउट प्लान अप्रूव कराने को यमुना अथारिटी में किया था आवेदन

पहले फेज को विकसित करने की जिम्मेदारी पिछले साल फिल्म निर्माता बोनी कपूर व भूटानी ग्रुप की कंसोर्टियम को मिल गई थी। पिछले वर्ष 23 दिसंबर को बोनी कपूर की कंपनी ने इसका लेआउट प्लान अप्रूव कराने को यमुना अथारिटी में आवेदन किया था, जिसे मंजूरी दे दी गई है।

करीब 1500 करोड़ का होगा निवेश

इस जमीन पर फिल्म निर्माण के लिए साउंड और लाइट के स्पेशल इफेक्ट वाले स्टूडियो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, विला, कार्यालय, आउटडोर लोकेशन आदि विकसित की जाएगी। साथ ही फिल्म निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों व विभिन्न प्रकार के सेट तैयार करने वाले सामान व इस इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने वाली इंडस्ट्री इन सात जोन में स्थापित की जाएंगी। बताया जा रहा है कि 230 एकड़ को डेवलप करने के लिए करीब 1500 करोड़ का निवेश होगा।

90 साल का लाइसेंस दिया गया है कंपनी को

फिल्म सिटी के लिए स्पेशल पर्पज कंपनी बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी का गठन किया गया है। बोनी कपूर कंपनी के चेयरमैन हैं। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसमें निदेशक के तौर पर शामिल हैं। कंपनी को फिल्म सिटी के निर्माण एवं संचालन के लिए 90 साल का लाइसेंस दिया गया है। कंपनी की कमाई से 18 फीसदी राजस्व यमुना प्राधिकरण को मिलेगा।

नोएडा के इस मेट्रो स्टेशन पर बनेंगे दो फुटओवर ब्रिज, पैदल यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

परिवहन विशेष न्यूज

बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन नोएडा प्राधिकरण ने बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास दो फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाने का फैसला किया है। इससे प्रतिदिन 80 हजार वाहनों की आवाजाही के बीच से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को राहत मिलेगी। एफओबी एमपी-3 रोड पर क्रासिंग के आसपास ही बनेंगे। प्राधिकरण की टीम ने पैदल यात्रियों के आने-जाने के समय व स्थान को लेकर अध्ययन शुरू कराया है।

नोएडा। बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन आने जाने के लिए प्रतिदिन लगने वाले यातायात जाम व तेज रफ्तार वाहनो के बीच से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को निजात दिलाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कवायद शुरू कर दी है। यहां रोजाना करीब 80 हजार वाहनों की आवाजाही रहती है। प्राधिकरण ने सेक्टर-37 क्रॉसिंग के आसपास दो फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाने का फैसला लिया है।

दोनों एफओबी एमपी-3 रोड पर क्रासिंग के आसपास ही बनेंगे। इसके लिए प्राधिकरण की टीम ने पैदल यात्रियों के आने जाने के समय व स्थान को लेकर अध्ययन शुरू कराया है। रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि किन दो स्थानों पर एफओबी बनाया जाए। प्राधिकरण सीईओ डॉ लोकेश एम ने बताया कि सेक्टर-37 क्रासिंग पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। हैवी ट्रैफिक फ्लो होता है।

यहां पर सड़क पार करने के लिए नहीं है कोई एफओबी यहीं से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, कालिंदी कुंज दिल्ली, डीएससी रोड की ओर वाहन आते जाते हैं। इसी क्रॉसिंग पर बाटेनिकल मेट्रो स्टेशन भी है, जहां पर ब्लू लाइन व मजेंटा लाइन है। भविष्य में बाटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक एक्वा मेट्रो की लिंक लाइन प्रस्तावित है। इन कारणों से मुसाफिरों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वर्तमान में यहां सड़क पार करने के लिए कोई एफओबी नहीं है।

जान हथेली पर लेकर लोग हर दिन ट्रैफिक के बीच करते हैं रोड पार

ऐसे में जान हथेली पर लेकर प्रतिदिन लोग भारी यातायात के दबाव के बीच रोड पार करते हैं। वाहनों के लगातार चलते रहने की वजह से यातायात पुलिस की मदद से ही लोग सड़क पार कर पाते हैं। इस कारण यहां जाम भी लगता है। उन्होंने बताया कि इस रोड पर सेक्टर-37 फ्लाईओवर और मेट्रो लाइन है। इसलिए इसकी स्टडी कराई जा रही है कि कहा पर एफओबी बनाया जाए।

ताकि इसका लोग प्रयोग कर सकें। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि फ्लाईओवर और मेट्रो संचालन में कोई परेशानी न हो साथ ही नई लाइन का अलाइनमेंट भी चेक किया जाएगा। एक बार अध्ययन रिपोर्ट आने के बाद टेंडर जारी होगा।

'ऑफिस में कुर्सी पर बैठे-बैठे दिल धोखा दे जाता है...', सेहत को कैसे रखें फिट? डॉक्टर ने बताए ये 9 प्वाइंट्स

परिवहन विशेष न्यूज

दिल की सेहत बनाए रखने के लिए सुबह की सैर योग और मेडिटेशन बेहद जरूरी है। रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज और हफ्ते में 5 दिन ब्रिस्क वॉक करें। सब्जियां फल नट्स और होल ग्रेन खाएं। सफेद चीजों जंक फूड और तले हुए खाने से बचें। पर्याप्त नींद लें तनाव कम करें और दोस्तों-परिवार के साथ समय बिताएं। धूमपान और शराब से बचें। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं और हाइड्रेटेड रहें।

नोएडा। दैनिक जागरण की विशेष श्रृंखला हृदय की बात न सिर्फ किसी की टूटती सांसों को सुरक्षित करने का अभियान है बल्कि घर बैठे या सड़क पर चलते-फिरते, नाचते-गाते अचानक से दिल में उठे दर्द के बाद व्यक्ति को अचेत अवस्था में जीवन बचाने की आस है।

अभियान की पहली किस्त में विशेषज्ञों के माध्यम से बताया गया था कि क्या है सीपीआर, कैसे इससे किसी का जीवन बचा सकते हैं और कौन सीपीआर दे सकता है। अभियान की दूसरी किस्त में हम विशेषज्ञ के माध्यम से बता रहे हैं कि जीवनशैली और खाना आदि के आधार पर कैसे हृदय की समस्याओं से बच सकते हैं?

ऑफिस में कुर्सी पर बैठे-बैठे दिल धोखा दे जाता है

नोएडा स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कार्डियक सर्जरी विभाग में डायरेक्टर डा. मनोज लूथरा ने बताया कि कई बार सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि शादी-पार्टी में कोई व्यक्ति नाचते गाते, कोई खेल के मैदान में दौड़ते हुए तो किसी का ऑफिस में कुर्सी पर बैठे-बैठे दिल धोखा दे जाता है। कुछ सेकेंड में सीपीआर नहीं मिलने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण खराब खान-पान और बिगड़ती जीवनशैली है। ऐसे में योग और सुबह की सैर के साथ पोषणयुक्त खाना फिट इंडिया-हिट इंडिया का मंत्र है।

काम की बातें

रोज व्यायाम करें

व्यायाम हृदय को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है। रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन ब्रिस्क वाक यानी तेज चाल में सैर करें। यह न केवल हृदय को स्वस्थ रखेगा, बल्कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्राल को भी ठीक रखता है। योग करना हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हैं। अगर जिम नहीं जा सकते, तो हल्के-फुल्के घरेलू व्यायाम जैसे स्ट्रेचिंग, डांसिंग, या सीढ़ियां चढ़ना उतरना शामिल करें।

भरपूर पोषण वाला खाना खाए

आप जो खाते हैं, वह सीधे दिल पर असर डालता है। इसलिए खाने में सब्जियां जैसे- पालक, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। फल में सेब, संतरा, अनार, जैसे फल खाएं। नट्स में बादाम, अखरोट और काजू का सेवन करें। ये अच्छे कोलेस्ट्राल को बढ़ाते हैं। होल ग्रेन में ब्राउन राइस, ओट्स और बाजरा जैसे अनाज का सेवन करें और दाल, राजमा, सोयाबीन भी खाएं। यदि नान वेज खाते है तो चिकन खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी।

सफेद चीजों से दूरी बनाएं

चीनी, मैदा, क्रीम और मक्खन का सेवन कम करें। ये चीजें हृदय की समस्याओं का कारण बन सकती हैं। जंक फूड और फ्राइड फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चिप्स आदि से बचें, तला हुआ और ज्यादा फैट वाला खाना कम मात्रा में खाएं।

पर्याप्त नींद लें

नींद की कमी हृदय के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। रोजाना 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। सोने और जागने का समय नियमित रखें। इससे तनाव भी कम होगा और हृदय स्वस्थ रहेगा।

तनाव कम लें

आज के समय में तनाव हृदय रोगों का एक बड़ा कारण बन चुका है। इसे कम करने के लिए, मेडिटेशन करें, खुद को पाजिटिव एक्टिविटी में व्यस्त रखें और अपनी भावनाओं को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करते रहें। कभी भी तनाव हो तो उस बात को ज्यादा देर तक दिमाग में न रखें। तुरंत दूसरे व्यक्ति को बताकर या चर्चा करके उसका समाधान निकालनें का प्रयास करें।

दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं

दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मेंटल और फिजिकल स्वास्थ्य बेहतर होता है, खुश रहना और हंसना हृदय के लिए बहुत फायदेमंद है और सामाजिक गतिविधियों में भाग लें और रिश्तों को मजबूत बनाएं।

धूमपान और शराब के सेवन से बचें

धूमपान और शराब का सेवन हृदय को कमजोर बनाता है। इन आदतों को छोड़कर आप अपने हृदय को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं।

नियमित स्वास्थ्य जांच करवाए

यदि आप नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं करा रहे हैं तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्राल का स्तर नियमित रूप से जांचते रहें। समय-समय पर डाक्टर से सलाह लें ताकि किसी भी समस्या को समय रहते रोका जा सके।

हाइड्रेटेड रहें

- भरपूर मात्रा में पानी पिएं। यह शरीर के टाक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और हृदय को भी स्वस्थ रखता है।

हृदय रोग विशेषज्ञ का कहना है कि फैट्स को पूरी तरह से छोड़ना सही नहीं है। शरीर को हेल्दी फैट्स की भी जरूरत होती है। इसके लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर चीजें खाएं जैसे मछली, अलसी के बीज और अखरोट व तली हुई चीजों की जगह भुनी हुई चीजें खाएं। यह फार्मूला बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण है।

रोजाना व्यायाम, योगासन व ध्यान सप्ताह में पांच बार ब्रिस्क वाक और संतुलित आहार एक लंबी व स्वस्थ जिंदगी के लिए जरूरी है।

उनका कहना है कि हृदय की समस्याओं से बचने के लिए स्वस्थ जीवनशैली और सही खानपान बेहद जरूरी है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तनाव मुक्त जीवन और सही आदतें अपनाकर हृदय को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं।

गौभक्त शैलेन्द्र पहलवान ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा। गौभक्त शैलेन्द्र पहलवान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की है ।राष्ट्रीय गोरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र पहलवान ने कहा कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। नहीं तो जेल भरो आंदोलन और नंगे पैर चलने की कसम खाई थी। एक माँ माह में 6 महीने दूध पिलाती है एक गौ माता हमारी जिंदगी भर भर दूध पिलाती है। योगी जी भी एक गौ रक्षक है। एक पुत्र अपनी मां का दर्द समझता है। गौरक्षक भाई अपनी जान पर खेल कर गौ माता की सेवा करते हैं। अपनी मां की सेवा तो बेटा करता है। इसके मूत्र से दवाइयां बनती हैं और इसके गोबर से औषधि और धूप बत्ती बनती है। प्राचीन काल में गौ माता की सेवा हमारे कृष्ण भगवान ने भी की थी ।पिछले दिनों राष्ट्रीय गौरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र पहलवान ने घोषणा करते हुए यहाँ तक कह दिया की यदि कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जाता तो वे अपने प्राण भी त्याग सकते हैं ।उन्होंने सरकार से निवेदन करते हुआ कहा है कि हमारी माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए । जिससे गो तस्करी और गौ हत्या पर पूरी तरह विराम लगे, बूचड़ खाना पर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिए।उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी को सम्बोधित करते हुए कहा की आप भी एक गौ रक्षक है, गौ माता को अपनी माता से बढ़कर मानते हैं, आपको हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा । शैलेंद्र पहलवान का कहना हैं कि एक मां कुछ समय तक दूध पिलाती है और गौ माता हमारी हमेशा हमें दूध पिलाती है । इसके लिए हमें प्राण त्याग ने पड़े तो हमारे लिए गर्व की बात है।

आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे पायेगी एकीकृत पेंशन योजना?

यूपीएस में स्विच करना एक बार तय हो जाने के बाद अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है। यूपीएस को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी किए गए विनियमों के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। 1 अप्रैल, 2025 वह तारीख है जिस दिन एकीकृत पेंशन योजना लागू होगी। यूपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी दी जाती है जो सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के लिए उनके औसत मूल वेतन के 50% के बराबर होती है। 10 से 25 साल तक की सेवा अवधि के लिए पेंशन आनुपातिक होगी। कम से कम 25 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी पूरी सुनिश्चित पेंशन के लिए पात्र होंगे। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारी की मृत्यु-पूर्व पेंशन के 60% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाएगी। जिन कर्मचारियों ने कम से कम दस साल तक काम किया है, उन्हें सेवानिवृत्ति पर प्रति माह 10, 000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। सेवानिवृत्त लोगों के लिए, यह एक सुरक्षा जाल की गारंटी देता है।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की जगह एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी है। यह टी के सुझावों पर आधारित है। सिफारिशें 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगी। यूपीएस के प्रस्ताव के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लाभों को एक साथ जोड़ा जाएगा। भारत में सेवानिवृत्ति योजना के लिए इस दूरदर्शी दृष्टिकोण का लक्ष्य सभी योग्य कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और दीर्घकालिक पेंशन प्रणाली है। यह सरकारी कर्मचारियों की स्वतंत्रता और पसंद को संरक्षित करने के साथ-साथ उन्हें दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत इस विकल्प का चयन करते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं, वे यूपीएस के अधीन हैं। वर्तमान और भावी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उनके पास वर्तमान एनपीएस योजना के साथ बने रहने या यूपीएस में स्विच करने का विकल्प है।

यूपीएस में स्विच करना एक बार तय हो जाने के बाद अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है। यूपीएस को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी किए गए विनियमों के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। 1 अप्रैल, 2025 वह तारीख है जिस दिन एकीकृत पेंशन योजना लागू होगी। यूपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी दी जाती है जो सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के लिए उनके औसत मूल वेतन के 50% के बराबर होती है। 10 से 25 साल तक की सेवा अवधि के लिए पेंशन आनुपातिक होगी। कम से कम 25 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी पूरी सुनिश्चित पेंशन के लिए पात्र होंगे। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारी की मृत्यु-पूर्व पेंशन के 60% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाएगी। जिन कर्मचारियों ने कम से कम दस साल तक काम किया है, उन्हें सेवानिवृत्ति पर प्रति माह 10, 000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। सेवानिवृत्त लोगों के लिए, यह एक सुरक्षा जाल की गारंटी देता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 25 साल तक काम किया है, उन्हें पेंशन की गारंटी दी जाती है। यह सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के लिए उनके औसत आधार वेतन का आधा हिस्सा लेकर निर्धारित किया जाता है। यूपीएस सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित पेंशन को मुद्रास्फीति के साथ अनुक्रमित करता है। महंगाई राहत के रूप में, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित है और सहायता श्रमिकों के बराबर है। मासिक वेतन का दसवां हिस्सा और महंगाई भत्ता प्रत्येक पूर्ण छह महीने की सेवा अवधि के लिए ग्रेच्युटी में जोड़ा जाता है। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों द्वारा उनके वेतन का दस प्रतिशत अभी भी योगदान दिया जाएगा। सरकार वर्तमान 14 प्रतिशत के बजाय 18.5 प्रतिशत का योगदान देगी। यह गारंटी देता है कि श्रमिकों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दबाव नहीं डाला जाएगा। जब कर्मचारी सेवानिवृत्ति तक पहुँचते हैं, तो यूपीएस गारंटीकृत भुगतान प्रदान करता है।

सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में, यूपीएस एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को उनके औसत मूल वेतन का 50% भुगतान करेगा, जब तक कि उन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर ली हो। जिन श्रमिकों ने दस साल से अधिक लेकिन पच्चीस साल से कम समय तक काम किया है, वे आनुपातिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। दस साल या उससे ज़्यादा की अर्हक सेवा के बाद, कर्मचारियों को हर महीने 10, 000 रुपये का न्यूनतम भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। यह भुगतान उस दिन से शुरू होगा, जिस दिन अगर वे काम करना जारी रखते, तो वे 25 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वालों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँच जाते। कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान धारक की मृत्यु की स्थिति में धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% पारिवारिक भुगतान मिलेगा। गारंटीकृत भुगतान और पारिवारिक भुगतान भी महंगाई राहत के लिए पात्र होंगे, जिसका निर्धारण उसी तरह किया जाएगा।

सेवारत कर्मचारियों के लिए, महंगाई राहत की गणना महंगाई भत्ते के समान ही की जाएगी। यूपीएस या गारंटीकृत भुगतान उस स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा जब कोई कर्मचारी इस्तीफा दे देता है या उसे सेवा से हटा दिया जाता है। पिछली पेंशन योजना के विपरीत, यूपीएस एक अंशदायी योजना है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, जबकि केंद्र सरकार, जो कि नियोक्ता है, 18% का योगदान करेगी। वह कोष, जिसे मुख्य रूप से सरकारी ऋण में निवेश किया जाता है, अंततः बाज़ार के रिटर्न के आधार पर भुगतान का निर्धारण करेगा। यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध दो विकल्प हैं। यूपीएस के विपरीत, एनपीएस बाज़ार से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित लाभों के सम्बंध में यूपीएस और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के बीच समानताएँ हैं। हालांकि, इसे वित्त पोषित करने का तरीक़ा बहुत अलग है।

यूपीएस को प्रत्येक वर्ष बजट से अपना सारा वित्त पोषण प्राप्त होता है, ओपीएस के विपरीत, जो कि पे-एज-यू-गो कार्यक्रम था कर्मचारी एनपीएस के माध्यम से सेवानिवृत्ति कोष का निर्माण कर सकते हैं, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है जिसे पहली बार 2004 में लागू किया गया था। जो लोग अधिक गारंटी वाली पेंशन की तलाश में हैं, उनके लिए यूपीएस एक विकल्प प्रदान करता है।

किआ सिरोस की प्राइस से 1 फरवरी को उठेगा पर्दा, पहले जान लिजिए किन फीचर्स से है लैस

परिवहन विशेष न्यूज

किआ सिरोस की कीमत का खुलासा किआ सिरोस की कीमतों का खुलासा 1 फरवरी 2025 को होने वाला है। यह सब-4 मीटर सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट बिल्कुल नई गाड़ी है। इसमें इतने बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से यह अपने सेगमेंट में कई मॉडल को पीछे छोड़ देती है। इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि Kia Syros किन एडवांस फीचर्स के साथ आती है।

नई दिल्ली। Kia Syros को 19 दिसंबर 2024 को पेश किया गया था। इस दौरान की इसकी कीमत को छोड़कर सभी फीचर्स का खुलासा कर दिया गया था। कोरियाई ऑटोमेकर किआ की यह सब-4 मीटर सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट एक नई गाड़ी है। इसमें इतने बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जो अपने सेगमेंट में कई मॉडलों को पीछे छोड़ देती है। Kia Syros की कीमतों (Kia Syros price) का खुलासा 1 फरवरी 2025 को किया जाएगा। आइए जानते हैं कि Kia Syros को किन फीचर्स से लैस किया गया है।

वैरिएंट और कलर ऑप्शन

Kia Syros को 6 वेरिएंट में पेश किया गया है, जो HTK, HTK (O), HTK+, HTX, HTX+, और HTX+ (O) है। इसे आठ कलर

ऑप्शन में लाया गया है, जो ग्लेशियर व्हाइट, स्पार्कलिंग सिल्वर, ग्रेविटी ग्रे, इंटेंस रेड, ऑरोरा ब्लैक, इंपीरियल ब्लू, प्यूटर ऑलिव और फ्रॉस्ट ब्लू है। वहीं, इसे मिंट ग्रीन एक्सेंट के साथ क्लाउड ब्लू/ग्रे थीम और मैट ऑरेंज एक्सेंट के साथ ब्लैक/ग्रे के साथ इंटीरियर थीम दिया गया है।

Kia Syros के फीचर्स

इसमें 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5 इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीट, फोर-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट, 64-रंग एम्बिएंट मूड लाइटिंग, 8-स्पीकर हरमन/कार्डन साउंड सिस्टम, सनशेड और सभी खिड़कियों के लिए ऑटो अप/डाउन कार्यक्षमता जैसे फीचर्स (Kia Syros features) दिए गए हैं।

Kia Syros के फ्रंट एंड में EV की तरह ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल, वर्टिकल स्टैक्ड LED DRLs, LED हेडलाइट्स और रीस्टाइल्ड बम्पर दिए गए हैं और साइड प्रोफाइल में फ्लश-टाइप डोर हैंडल और 17-इंच एलॉय व्हील को शामिल किया गया है।

Kia Syros के सेफ्टी फीचर्स

किआ इंडिया अपनी गाड़ियों में बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स देने के लिए जानी जाती है। कुछ ऐसा ही Kia Syros में भी देखने के लिए मिला है। इसमें छह एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, 360-डिग्री कैमरा, डुअल डैशकैम सेटअप, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) और लेवल-2 ADAS जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं।

Kia Syros का इंजन

किआ सिरोस को दो इंजन ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है, जो 1-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल है। इसका पेट्रोल इंजन 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसका डीजल इंजन 114 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है।

फरवरी 2025 में लॉन्च हो सकती है ये 4 कार, लिस्ट में किआ से लेकर ऑडी की गाड़ियां शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

फरवरी 2025 कार लॉन्च फरवरी 2025 में भारतीय बाजार में चार गाड़ियां एंट्री मारने जा रही है। हम यहां पर आपको इनके बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में Kia Syros Audi RS Q8 Performance MG M9 और MG Cyberster शामिल है। इनमें से MG M9 और MG Cyberster को ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किया गया था।

नई दिल्ली। ऑटो एक्सपो 2025 खत्म होने के बाद फरवरी में ज्यादा गाड़ियां नहीं लॉन्च होने वाली है। फरवरी 2025 में चार गाड़ियां लॉन्च होने वाली है, जिसमें Kia, Audi और MG की गाड़ियां शामिल है। आइए जानते हैं कि फरवरी में लॉन्च होने वाली गाड़ियों के बारे में।

Kia Syros

लॉन्च की तारीख: 1 फरवरी, 2025

एक्सपेक्टेड कीमत: 9.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Kia Syros सबकॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो इस सेगमेंट में एक गाड़ी है। इसे दिसंबर में पेश किया जा चुका है और अब इसकी कीमतों का खुलासा 1 फरवरी 2025 को किया जाएगा। इसे टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। सिरोस की बुकिंग चल रही है और डिलीवरी फरवरी के मध्य से शुरू होगी।

इसमें 12.3 इंच के दो डिस्प्ले, आगे और पीछे दोनों तरफ के यात्रियों के लिए हवादार सीटें और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। पैसेंजर की सेफ्टी के लिए Syros में छह एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे बेहतरी फीचर्स दिए गए हैं।

Audi RS Q8 Performance

लॉन्च की तारीख: 17 फरवरी, 2025

एक्सपेक्टेड कीमत: 2 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम)

ऑडी अपनी फ्लैगशिप परफॉरमेंस-ड्रिवन SUV, RS Q8 का अपडेटेड वर्जन भारत में लॉन्च करने जा रही है। इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। इसमें 4-लीटर टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 640 PS की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

Audi RS Q8 Performance महज 3.6 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 05 किमी प्रति घंटा है। इसमें 12.3-इंच इंफोटेनमेंट यूनिट, फोर-ज़ोन ऑटो AC, 17-स्पीकर बैंग और ओल्फ़सेन साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और कनेक्टेड कार तकनीक जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

MG M9

MG ने अपनी इस ऑल-इलेक्ट्रिक MPV को ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किया है। इसे

कार निर्माता के सिलेक्ट डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा। इसमें 90 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो सिंगल चार्ज में 430 किमी तक की ड्राइव रेंज देगा।

MG M9 में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेशन और आठ मसाज मोड के साथ पावर्ड फ्रंट और सेकंड-रो सीटें, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 12-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। पैसेंजर की सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसी सुविधाएं दी गई है।

MG Cyberster

MG M9 के साथ ही Cyberster को भी ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किया गया था। यह JSW MG मोटर की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है। इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है। इसे भी MG सेलेक्ट डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा।

MG Cyberster के डुअल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेश किया गया है। एमजी मोटर की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी यह इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार महज 3.2 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। इसमें 77 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है, जो सिंगल चार्ज में 570 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है।

यामाहा आर3 और एमटी03 को सस्ते में खरीदने का मौका, एक लाख रुपये से ज्यादा होगी बचत

परिवहन विशेष न्यूज

यामाहा ने भारतीय बाजार में अपनी दो बाइक की कीमतों में कटौती की है। यह दोनों मोटरसाइकिल Yamaha R3 और Yamaha MT 03 है। इन दोनों की कीमतों को 1.10 लाख रुपये तक कम किया गया है। Yamaha R3 एंट्री-लेवल सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल है तो Yamaha MT 03 पावरफुल हाइपर नेकेड स्ट्रीटफाइटर बाइक है। इन दोनों के ही अपडेटेड वर्जन साल 2025 के मध्य तक लॉन्च हो सकते हैं।

नई दिल्ली। इंडिया यामाहा मोटर ने अपनी दो मोटरसाइकिल की कीमतों को कम कर दिया है। कंपनी अपनी Yamaha R3 और Yamaha MT 03 की कीमतों को 1 फरवरी से कम करने जा रही है। यामाहा की इन दो बाइक की कीमतों में इतनी कटौती की गई है कि उसमें आप एक 100cc वाली कंप्यूटर बाइक खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कि Yamaha R3 और Yamaha MT 03 की कीमतों में कितनी कमी की गई है और यह किन फीचर्स के साथ आती है।

Yamaha R3 और Yamaha MT 03 की नई कीमत

यामाहा की इन दोनों मोटरसाइकिल की कीमतों में 1.10 लाख रुपये तक की कटौती की गई है। इसके बाद अब Yamaha R3 की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 3,59,900 रुपये हो गई है, जो पहले की कीमत 4,69,900 रुपये थी। वहीं, Yamaha MT 03 की दिल्ली में नई एक्स-शोरूम कीमत 3,49,900 रुपये हो गई है, जो पहले की कीमत 4,59,900 रुपये से कम है। इन दोनों बाइक के नए मॉडल को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया जा चुका है, जिन्हें साल 2025 के मध्य तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है।

दोनों बाइक के फीचर्स

Yamaha R3

यह एक एंट्री-लेवल सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल है, जो इस सेगमेंट एक बेंचमार्क रही है। इस बाइक को डिजाइन, ट्रैक-ओरिएंटेड हैंडलिंग और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसमें 321cc ट्विन-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 40.8 bhp की पावर और 29.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें टेलिस्कोपिक फॉर्क, प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक, डुअल चैनल ABS जैसे

फीचर्स दिए गए हैं।

Yamaha MT 03

यह एक पावरफुल हाइपर नेकेड स्ट्रीटफाइटर मोटरसाइकिल है। MT 03 में अपराइट राइडिंग पोजीशन, मास-फॉरवर्ड बॉडी डिजाइन और ट्विन-आई LED हेडलाइट्स जैसे फीचर्स से लैस किया गया है। इसमें 321cc 4-स्ट्रोक, लिक्विड-कूल्ड, DOHC, 4-वाल्व इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 42 PS की पावर और 29.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

क्यों कम हुई कीमत

भारतीय बाजार में प्रीमियम मोटरसाइकिल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। जिसे देखते हुए कंपनी अपनी इन दोनों बाइक की कीमतों को कम किया गया है। यामाहा की R3 और MT-03 की कीमत में कटौती के बाद भारत के तेजी से बढ़ते प्रीमियम मोटरसाइकिल बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। यह दोनों ही बाइक बेहतर परफॉर्मेंस, डिजाइन और रेसिंग फीचर्स के साथ आती है।

एमजी मोटर के चाहने वालों को झटका, बेस वेरिएंट छोड़कर बाकी सभी के बढ़े दाम

परिवहन विशेष न्यूज

एमजी मोटर की कीमत में बढ़ोतरी एमजी मोटर की गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसकी इलेक्ट्रिक और ICE दोनों गाड़ियों की कीमत को बढ़ाया गया है। MG की तरफ से भारत में पेश की जाने वाली सभी गाड़ियों के बेस मॉडल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है लेकिन सभी वेरिएंट की कीमतों को बढ़ा दिया गया है।

नई दिल्ली। MG Motor ने अपनी सभी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले कंपनी जनवरी के शुरुआत में अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। इस बार कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 90 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है। ZS EV की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत में 89,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। आइए जानते हैं कि इसके Hector, Astor और Comet EV की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की गई है।

MG ZS EV

MG Motor ZS EV को भारतीय बाजार में 6 वेरिएंट में पेश करती है। यह 18.98 लाख रुपये से 26.63 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत में आती है।

Executive: इसकी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह 18,98,000 रुपये में आती है।

Excite Pro: इस वेरिएंट की कीमत में 49,800 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी कीमत 20,47,800 रुपये है।

Exclusive Plus: 61,000 रुपये तक दाम बढ़े है। अब इसकी कीमत 25,14,800 रुपये है।

Exclusive Plus Ivory: 61,000 रुपये तक कीमत बढ़ी है। अब इसकी कीमत 25,34,800 रुपये है।

Essence: इस वेरिएंट की कीमत 89,000 रुपये तक बढ़ी है। अब इसकी कीमत 26,43,800 रुपये है।

Essence Ivory: इसकी कीमत भी 89,000 रुपये तक बढ़ी है। अब यह 26,63,800 रुपये की हो गई है।

MG Comet EV

कंपनी MG Comet EV को पांच वेरिएंट में भारतीय बाजार में पेश करती है। यह भारत में 7 लाख रुपये से 9.67 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में आती है।

Executive: इस वेरिएंट की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह 6,99,800 रुपये में आती है।

Excite: इसकी कीमतों में 12,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसकी कीमत अब 8,20,000 रुपये हो गई है।

Excite FC: इसकी कीमत 17,000 रुपये बढ़ी है। अब यह 8,72,800 रुपये की हो गई है।

Exclusive: इस वेरिएंट की कीमत में 14,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी कीमत 9,25,800 रुपये हो गई है।

Exclusive FC: इसकी कीमत 19,000 रुपये बढ़ी है। अब यह 9,67,800 रुपये की कीमत में उपलब्ध है।

MG Astor

कंपनी इसे 10 वेरिएंट में भारत में पेश करती है। इसकी भारत में एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से लेकर 18.35 लाख रुपये में उपलब्ध है।

मैनुअल वेरिएंट

Sprint: यह इसका बेस वेरिएंट है, इसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह भारत में 9,99,800 रुपये में उपलब्ध है।

Shine: इस वेरिएंट की कीमत में 12,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह अब 12,11,800 रुपये में उपलब्ध है।

Select: इसकी कीमत को 13,000 रुपये बढ़ाया गया है। यह अब 13,43,800 रुपये की हो गई है।

Sharp Pro: इसकी कीमत 21,000 रुपये बढ़ी है। यह अब 15,20,800 रुपये तक की हो गई है।

ऑटोमेटिक वेरिएंट

Select Ivory CVT: इस वेरिएंट की कीमत में 14,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। इसकी कीमत अब 14,46,800 रुपये हो गई है।

Sharp Pro Ivory CVT: इसकी कीमत 23,000 रुपये बढ़ी है। अब इसकी कीमत 16,48,800 रुपये हो गई है।

Savvy Pro DT Ivory CVT: इसकी कीमत में 24,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह अब 17,45,800 रुपये की हो गई है।

Savvy Pro Sangria DT CVT: यह भी 24,000 रुपये महंगी हो गई है। इसकी कीमत अब 17,55,800 रुपये हो गई है।

Savvy Pro Sangria DT 6-AT: इसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसकी कीमत पहले की तरह ही 18,34,800 रुपये है।

ब्लैकस्ट्रोम वेरिएंट

MT Blackstorm: इस वेरिएंट की कीमत में 13,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह अब 13,77,800 रुपये में उपलब्ध है।

CVT Select Blackstorm: इसकी कीमत 14,000 रुपये बढ़ी है। यह अब 14,80,800 रुपये की कीमत में मिलेगी।

MG Hector

MG Motor भारतीय बाजार में Hector को 13 वेरिएंट में पेश करती है। इसे पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाता है। इसकी भारतीय बाजार में एक्स-शोरूम कीमत 14 लाख रुपये से 22.89 लाख रुपये है।

Style: यह Hector का बेस वेरिएंट है। इसकी कीमतों किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह अब भी 13,99,800 रुपये में उपलब्ध है।

Shine Pro: इस वेरिएंट की कीमत 33,000 रुपये बढ़ी है। यह अब 16,73,800 रुपये में उपलब्ध है।

Select Pro: इसकी कीमत में 35,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसकी कीमत अब 18,07,800 रुपये हो गई है।

Smart Pro: यह वेरिएंट का दाम 38,000 रुपये बढ़ा है। यह अब 19,05,800 रुपये की हो गई है।

Sharp Pro: इसकी कीमत 41,000 रुपये बढ़ गई है। इसकी कीमत अब 20,60,800 रुपये हो गई है।

CVT Petrol

Shine Pro: इस वेरिएंट की कीमत 30,000 रुपये बढ़ी है। यह अब 17,71,800 रुपये की हो गई है।

Select Pro: इसकी कीमत 38,000 रुपये बढ़ी है। यह अब 19,33,800 रुपये की हो गई है।

Sharp Pro: इसकी कीमत में 31,000 रुपये बढ़ी है। यह अब 21,81,800 रुपये की हो गई है।

Savvy Pro: इस वेरिएंट की कीमत में 39,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसकी कीमत अब 22,88,800 रुपये हो गई है।

Diesel MT

Shine Pro: इस वेरिएंट की कीमत 45,000 रुपये बढ़ी है। अब इसकी कीमत 18,57,800 रुपये पहुंच गई है।

Select Pro: इसकी कीमत में 43,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब यह भारत में 19,61,800 रुपये की हो गई है।

Smart Pro: इसका दाम 31,000 रुपये बढ़ा है। यह अब भारतीय बाजार में 20,60,800 रुपये की हो गई है।

Sharp Pro: इस वेरिएंट की कीमतों को नहीं बढ़ाया गया है। यह पहले की तरह ही 22,24,800 रुपये में उपलब्ध है।

कैसे खरीदें बैंक की नीलामी में कार, आधी से भी कम कीमत में मिलेगी चमचमाती गाड़ी

परिवहन विशेष न्यूज

बैंक नीलामी कारें खरीदें आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो कार तो लोन पर ले लेते हैं लेकिन उसकी EMI समय पर चुका नहीं पाते है। ऐसे लोगों की कार को बैंक जब्त कर लेती है और उसकी भरपाई वह नीलामी के जरिए करती है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि आप बैंक के जरिए नीलाम की जाने वाली कार को कैसे खरीद सकते हैं।

नई दिल्ली। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डाउन पेमेंट पर नई कार खरीद लेते हैं। वह उस कार की EMI समय पर चुका नहीं पाते हैं। ऐसी गाड़ियों को बैंक या फाइनेंस कंपनियां जब्त कर लेती है। इन गाड़ियों को बैंक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से नीलाम करके अपनी बची हुई रकम की रिकवरी करती है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से बैंक के जरिए नीलाम होने वाली गाड़ियों को खरीद सकते हैं।

नीलामी वाली गाड़ियों का फायदा

बैंक के जरिए होने वाली गाड़ियों की नीलामी से लोगों को काफी फायदा होता है। दरअसल, इससे लोगों को कम कीमत में अच्छी कार मिल जाती है। इसके साथ ही उन्हें कार की रजिस्ट्रेशन और डाक्युमेंट के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। नीलामी की प्रक्रिया पूरी होते ही बैंक खरीदार को कार के सभी डॉक्युमेंट दे देती है।

बैंक की नीलामी वाली कार खरीदने का तरीका

कैसे ढूंढ़े नीलामी वाली कार?

बैंक की तरफ से नीलाम होने वाली कारों की जानकारी बैंक अपनी वेबसाइट या फिर Banknet नाम के पोर्टल पर जारी करती है। इसके साथ ही वह यह भी जारी करते हैं कि उस गाड़ी की नीलामी कब होगी। वहीं, कई बैंक के पास तो इसके लिए एक रेपजेशन या नीलामी विभाग भी होता है। यह डिपार्टमेंट जब्त की गई प्रॉपर्टी या वाहनों को नीलाम करने का का काम करते हैं। इसके अलावा, आप eAuctions India और IBA ऑक्शन प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर गाड़ियों की नीलामी की जानकारी को देख सकते हैं।

नीलामी में शामिल होने के लिए क्या करें?

गाड़ियों के लिए होने वाली नीलामी में शामिल होने के लिए आपको पहले Banknet, eAuctions India या IBA ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

नीलामी में शामिल होने के लिए आपको अपनी आईडी प्रमाण, बैंक डिटेल्स और किसी भी अन्य जरूरी डॉक्युमेंट को सबमिट करना होगा।

नीलामी का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसके लिए आपको खुद को पहले तैयार करना होगा।

गाड़ियों की नीलामी में शामिल होने के लिए अपना एक बजट जरूर बनाएं। उत्साह में बढ़कर अपना अधिक खर्च करने से बचें।

नीलामी जीतने के बाद क्या करें?

अगर आप बैंक की तरफ से नीलाम की जा रही कार को जीत जाते हैं, तो आपको ईएमडी के समायोजन के बाद उसकी गाड़ी के लिए अमाउंट का भुगतान करना पड़ेगा। आपकी तरफ से नीलामी राशि को जमा करने के बाद बैंक की तरफ से गाड़ी को लेने और हस्तांतरण की जरूरतों को पूरा करने के निर्देश देगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीलाम हुई कार आपकी हो जाएगी।

नीलामी से पहले क्या करें?

कार की नीलामी में शामिल होने से पहले आप उसके बारे सभी जानकारी को जरूर चेक कर लें।

बहुत से बैंक नीलामी से पहले वाहन को टेस्टिंग की परमिशन भी देते हैं।

इस दौरान उस कार की कंडीशन को आराम से चेक कर सकते हैं।

नीलामी में शामिल होने से पहले बैंक के नियम और शर्तों के बारे में जरूर जानें।

आप नीलामी में शामिल होने से पहले उस कार की जांच मैकेनिक से भी जरूर करवाएं।

इतिहास लेखन में एआइ का उपयोग

विजय गर्ग

इतिहास अगर एक व्यंजन है तो उसकी कच्ची समग्री है सूचना। हालांकि इसमें रसोइये' की भी भूमिका तो है ही, किंतु बिना शक्कर के मीठापन आए कैसे। अतः सूचना जिसे तथ्य कह लीजिए या फिर स्रोत कह लीजिए, इसके बिना 'इतिहास की रचना संभव नहीं है। स्रोत जितना प्रामाणिक, विस्तृत और सटीक होगा, इतिहास का स्वरूप भी उतना ही सच्चा, समावेशी व पारदर्शी होगा। हालांकि यह मानवीय दुविधा तो तब भी बनी ही रहेगी कि तथ्यों का उपयोग कैसे किया जा रहा अतीत की मिट्टी में वर्तमान की आवश्यकता मिलाकर उसे विचार की आग में पकाने वाले मूर्तिकार तो तब भी इतिहास का सौंदर्य कलुषित कर ही देंगे, पर फिर यह विकल्प भी होगा कि उसके समानांतर कई अन्य मूर्तियां भी सजाई जा सकेंगी। ऐसे में पाठक के विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।

स्त्रोतों को प्राप्त करने, उसे जांचने और उसके सटीक उपयोग में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेस' यानी एआइ भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि यूजीसी ने तो 'डिजिटल हिस्ट्री' और 'एआइ इन हिस्टोरिकल रिसर्च' जैसे पाठ्यक्रम का भी प्रस्ताव रखा है। प्रौद्योगिकी पहले भी इतिहास लेखन में भूमिका निभाता रहा है, एआइ से यह उम्मीद और बढ़ गई है।

गुत्थियों को सुलझाने में उपयोगी : आर्टिफिशियल इंटेलिजेस अपनी पुरानी पीढ़ी की तकनीकों से इस मामले में अलग है कि यह केवल सूचनाओं का संग्रह ही नहीं करती, बल्कि इसके उपयोग की दक्षता से भी यह युक्त है। इसमें कुछ-कुछ मानव बुद्धि जैसी क्षमता है और जिसकी व्यापकता कहीं ज्यादा है ऐसे में स्रोतों के अभाव में इतिहास का जी हिस्सा अंधेरे में है, उस पर थोड़ी रोशनी डाली जा सकती है। मसलन अगर एआइ ने प्राचीन भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में विशिष्टता हासिल कर ली तो न जाने इतिहास की कितनी तहें खुल जाएंगी। भारतीय इतिहास के सबसे पुराने विवादों में से एक 'आर्य विवाद' भी इससे काफी कुछ सुलझ सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त एक शक्तिशाली मशन तमाम भाषाओं का अन्वेषण कर उनकी समानता असमानता को अधिक सटीकता से वर्गीकृत कर सकती है। इससे यह गिरह भी खुल सकती है कि जिस 'बर्च वृक्ष' के उपयोग के सहारे

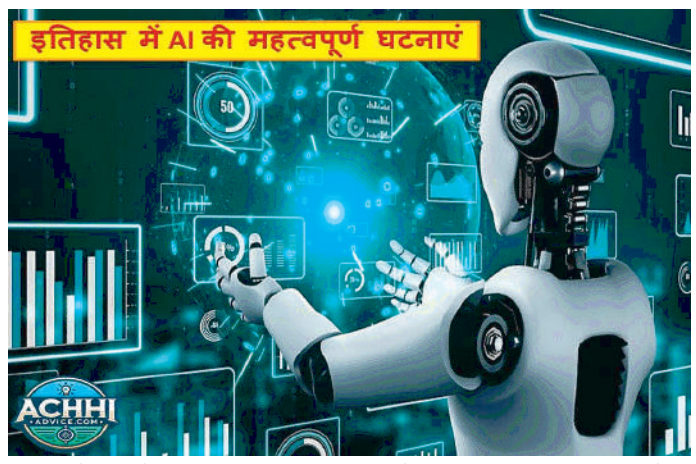

जाइलस ने आर्यों के मूल स्थान की किसी आल्प्स क्षेत्र में खोजा, वह कितना सही है। इन गुत्थियों को सुलझाने में निश्चित ही एआई बहुत काम आ सकती है। प्राचीन भाषाओं व लिपियों के अध्ययन से शायद एआई इतनी सक्षम हो जाए कि वह हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ने में सहायक साबित हो सके। ऐसे में इस सभ्यता के कई पहलू ठीक से सामने आ सकेंगे। इतिहास का पुनरावलोकन इसके अतिरिक्त एआइ चूंकि बहुत तेजी से असीमित सूचनाओं का विश्लेषण कर सकती है, इसलिए इससे शोधकर्ताओं को उन आंकड़ों को वर्गीकृत करने और उसका एक पैटर्न निश्चित करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। तकनीकी रूप से कहें तो 'टेक्स्ट माइनिंग के माध्यम से अतीत तक बेहतर ढंग से पहुंचा जा सकता है। सूचनाओं के ढेर में काम की सूई ढूंढना, एआइ के लिए सेकेंड भर का काम होगा। उदाहरण के लिए 'राष्ट्रीय आंदोलन' के विशाल डाटाबेस में 'अंगिका भाषी की भागीदारी की पहचान तब एकदम आसान हो जाएगे, तब संथाल विद्रोह से लेकर भारत छौड़ी आंदोलन तक का निश्चित पैटर्न हमारे सामने होगा। ठीक इसी प्रकार स्रोतों को जांचने, वैसे ही अन्य स्रोतों को सुझाना, उन स्रोतों के उपयोग के खतरों से आगाह करना, उस पर पहले की जा चुकी प्रामाणिक टिप्पणियों को प्रस्तुत करना और सबसे बढ़कर लेखक के व्यक्तित्व तथा उसके विचार को पाठ के साथ प्रस्तुत कर देने में एआइ एक सफल माडल हो सकता है। निश्चित ही इससे शोधकर्ताओं का काफी कीमती समय बचेगा और वह अधिक ऊर्जा से अपने 'सत्य' की तरफ बढ़ सकेंगे। फिर एआइ ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में काफी सहायक हो सकता है। इसके अलावा, इन दस्तावेजों तक पहुंच भी आसान हो सकेगी तथा उसका उपयोग भी सरल हो जाएगा। इतिहास में बढ़ेगी रुचि बढ़कर स्कूल-कालेज में इतिहास की पढ़ाई को रुचिकर बनाने में एआइ की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह अतीत के इनपुट्स के आधार पर एक 'कृत्रिम अतीत' की रचना कर सकता है। भीमबेटका की गुफाओं में चित्र बनाते आरंभिक मानव के वीडियो से विद्यार्थी निश्चित ही उस समय को अधिक समीप से जान सकेंगे। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की श्रेष्ठता भी एआई उन्नत ग्राफिक्स के साथ प्रदर्शित कर सकता है, जिससे विद्यार्थियों को इसे समझने में आसानी ही सकती है। इतना ही नहीं, युद्ध इत्यादि प्रसंग को भी अधिक जीवंतता से प्रस्तुत किया जा सकेगा। एआइ इतिहास विषय को पढ़ाई को रुचिकर बना सकता है और विद्यार्थियों के मन से इस विषय के कठिन व शुष्क होने का ठप्पा हटा सकता है।

इतनी आशाओं के बाद भी हमें इस नई प्रौद्योगिकी के प्रति सचेत रहना होगा। ऐसा न हो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कृत्रिम अतीत की रचना में किया जाने लगे। इस संदर्भ में भी जागरूक रहना होगा कि कहीं किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर मशीन विशाल सूचनाओं को एक निष्कर्ष में न बदलने लग जाए और यह भी कि ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास लेखन सूचनाओं का प्रसंस्करण भर नहीं है, बल्कि इसके लिए एक साफ-सुथरा मानव हृदय भी चाहिए। मानव जाति को अपने पूर्वजों को ईमानदार कहानी कहने का महान दायित्व केवल मशीन के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए।

सेहतमंद आहार को बनाएं पहली पसंद

विजय गर्ग

भोजन के चुनाव में खास ख्याल रखना चाहिये कि वह स्वाद तो हो, साथ ही सेहत के लिए लाभकारी भी हो। उसमें शामिल पदार्थ नुकसानदेह न हों। जिस टेस्टी खाद्य पदार्थ या ड्रिंक से सेहत को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा हो तो उससे परहेज ही बेहतर है। इसके बजाय उनके हेल्दी विकल्प इस्तेमाल करें।

खाने की मेज पर अपनी पसंद के व्यंजन देख अकसर भूख जाग जाती है। लेकिन यही स्वादिष्ट व पसंदीदा भोजन कभी-कभी हमारा दुश्मन भी हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर हम सिर्फ बात पर ध्यान देते हैं कि क्या खाना चाहिए। लेकिन क्या नहीं खाना चाहिए इस पर कम ही ध्यान दिया जाता है। ऐसे में भोजन हमें खुद पर नियंत्रण रख ग्रहण करना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ आपके खाने की मेज पर ही मौजूद होते हैं जिनसे परहेज़ आपको स्वस्थ रखने में बड़ी मदद कर सकता है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की वक्ता और डायटिशियन विक्टोरिया टेलर ने कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थों को इंगित करते हुए बताया है कि अगर आप उन्हें अपनी दिनचर्या से दूर कर लें तो काफी फायदा हो सकता है।

एनर्जी ड्रिंक्स

आजकल तनाव और थकान को कम करने में मदद देने वाले ढेर सारे एनर्जी ड्रिंक बाज़ार में आ गए हैं। जिसका सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना यह पता किए कि उसमें क्या तत्व मिलाए गए हैं। एनर्जी ड्रिंक फायदेमंद होती हैं, यदि उन्हें पीने के जोखिमों के बारे में जागरूकता के साथ उपयोग किया जाये। ज्यादातर में एनर्जी ब्लेंड जैसे कि कैफीन, टॉरिन, और ग्लूकोरोनोलैक्टोन इतनी मात्रा में होते हैं जो कि सुरक्षित नहीं होते। बहुत अधिक मात्रा में लें तो ये हानिकारक हो सकते हैं।

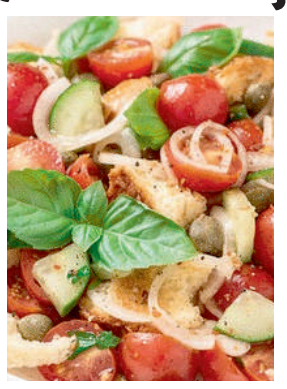

पैकेज्ड जूस

फलों का ताजा निकाला गया जूस फायदेमंद होता है। लेकिन आज पैकेज्ड जूस भी आसानी से उपलब्ध हैं। जूस के पैकेट पर फलों का इस्तेमाल करके बनाया गया जूस लिखा होता है। लेकिन इस जूस को तैयार करने के लिए फलों को निचोड़कर उनसे जूस निकाल लिया जाता है और इसे आमतौर पर लंबे समय तक टैंकों में स्टोर करके रखा जाता है। इससे जूस लगभग फ्लेवर और पोषण मुक्त हो जाता है। फिर इसमें फ्लेवर और चीनी मिलाए जाते हैं और इसी स्वाद का हम आनंद ले रहे होते हैं।

सफेद ब्रेड

बच्चों की टिफिन से लेकर दफ्तर के लंच बॉक्स तक में ब्रेड की डिशेज रहती हैं। क्योंकि इन्हें बनाना आसान होता है। लेकिन सफेद ब्रेड अन्य ब्रेड विकल्पों की तुलना में फाइबर और प्रोटीन के मामले में बहुत खराब होता है। इसकी जगह पूरी तरह से गेहूं से बने, ब्राउन ब्रेड कुछ हद तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फाइबर हमारे शरीर के पाचन को ठीक रखता है। सफेद ब्रेड में फाइबर का अभाव होता है। इससे शरीर में शुगर बढ़ने का भी डर होता है।

प्रोसेस्ड मीट

प्रोसेस्ड मीट में संतृप्त वसा और नमक होता है, जिससे आंत्र कैंसर होने की आशंका होती है। इसका उपयोग बाहर बने जंक फूड्स के साथ-साथ आज घरों में भी हो रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रोसेस्ड मीट को कैंसर के खतरे से जोड़ा है। क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में सोडियम और संतृप्त वसा हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकती है। वहीं वजन बढ़ने और मधुमेह का कारण बन सकती है।

टोस्ट, जैम को भी ना कहें

टोस्ट पर जैम , आमतौर पर हर घर में खाया जाता है। बच्चों को तो यह विशेष रूप से पसंद होता है। लेकिन इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। इनकी जगह पर केला खाने से आपको ज़्यादा विटामिन, मिनरल, फाइबर मिलेंगे। जैम की जगह फलों को डाइट में शामिल करें। अपने अनाज में कुछ फल काट कर डालें, जैम की जगह टोस्ट पर केला आदि फल खाएं। सैंडविच में सलाद डालें तो बेहतर है।

चॉकलेट की जगह मेवे

चॉकलेट एक ट्रीट के रूप में ठीक है, लेकिन रोज़ाना नाश्ते के लिए, बिना नमक वाले नट्स या ताजे फल इस कमी को पूरा करने के बेहतर तरीके हैं। नट्स में विटामिन और मिनरल के साथ-साथ प्रोटीन और फाइबर भी होते हैं और संतृप्त वसा कम होती है, जिससे ये आपके कोलेस्ट्रॉल स्तर और दिल के स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं। नट्स लगभग 30 ग्राम ही लें।

एक स्वस्थ आहार में सभी पोषक तत्व और खाद्य समूह को शामिल किया जा सकता है। उनमें संतुलन बनाकर आप अपनी आधी प्लेट फलों और सब्जियों से भरें और एक चौथाई से थोड़ा अधिक अनाज से। इन स्वस्थ व पसंदीदा विकल्पों से भी आप भोजन की मेज सजा सकते हैं

नई पीढ़ी में कार्य जीवन संतुलन

विजय गर्ग

वर्ष 1997 और 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी, जिसे जेनरेशन जेड भी कहा जाता है, वह वैश्विक कार्यबल को प्रभावित करने की स्थिति में आ गई है। ये वैश्विक उपभोक्ताओं का लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक कार्यबल का 25 प्रतिशत हिस्सा हैं। इस वर्ष के अंत तक इस पीढ़ी का भारत के कार्यबल का 27 प्रतिशत हिस्स बनने का अनुमान है। हालांकि हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जेनरेशन जेड की स्थायी और दीर्घकालिक रोजगार प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक छह कंपनियों में से एक इस पीढ़ी के नए कर्मचारियों को नियुक्त करने में संकोच कर रही है। ये रुझान कार्यबल में उनकी तैयारी की लेकर चिंता उत्पन्न करते हैं।

एक संबंधित अध्ययन प्रमुख तीन मुख्य कारणों की और इशारा करते हैं- प्रतिक्रिया का विरोध जबाबदेही और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की कमी एवं रिमोट वर्क के लिए प्राथमिकता 'गैलप' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 55 प्रतिशत नियोक्ताओं ने रचनात्मक प्रतिक्रिया को स्वीकार न करने की प्रवृत्ति को प्रमुख चुनैती माना है। यह प्रतिक्रिया प्रतिरोध उनके विकास, अनुकूलन क्षमता और सुधार को प्रभावित करता है। जबकि जेनरेशन जेड कर्मचारी प्रतिक्रिया को आलोचना के रूप में देखते हैं। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि प्रतिक्रिया व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है प्रतिक्रिया को स्वीकार करने और उस पर कार्य करने में

असमर्थता उनके करियर की उन्नति में बाधा डाल सकती है और उनके लिए उन संगठनों में समायोजन कठिन है, जहाँ सुधार को महत्व दिया जाता है।

'कैरियर बिल्डर' के एक शोध में यह भी सामने आया है कि कुछ जेनरेशन जेड कर्मचारी 'माउस जिंगल' जैसे व्यवहार में संलग्न होते हैं, जहां के

वास्तविक कार्य से बचते हुए सक्रिय दिखने के लिए अपने कंप्यूटर माउस में हेरफेर करते हैं। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसर 45 प्रतिशत जेनरेशन जेड पेशेवरों ने कठिन कार्यों से बचने या प्रगति का भ्रम पैदा करने के लिए ऐसी युक्तियों का उपयोग करना स्वीकार किया है 'डेलायट' ने पाया है कि 44 प्रतिशत जेनरेशन जेड कर्मचारी रोजगार के पहले दो वर्षों के भीतर नौकरी बदलने की उम्मीद करते हैं। पुरानी पीढ़ियां कई वर्षों तक एक ही कंपनी के साथ रहती थीं, जबकि जेनरेशन जेड तेजी से नए अवसरों की तलाश करती है यह प्रवृत्ति उन नियोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है जिन्हें अपने कार्यबल से स्थिरता और वैर्धकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

इसके अतिरिक्त, गैलप के 2021 के सर्वेक्षण से पता चला है कि 58 प्रतिशत जेनरेशन जेड कर्मचारी 'रिमोर्ट वर्क' पसंद करते हैं, जो यह लचीलेपन के लिए कार्यबल की बदलती अपेक्षाओं को दर्शाता है। हालांकि इसके कार्य- जीवन संतुलन जैसे लाभ भी हैं, तो वहीं यह टीम सहयोग व जवाबदेशी के लिए चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है लिहाजा जी नियोक्ता लचाली कार्य व्यवस्था की पेशकश करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, उन्हें जेनरेशन जेड की शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें साथ बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।

दीर्घकालिक करियर लक्ष्य इन चुनौतियों के समाधान के लिए इस पीढ़ी को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार, जो कर्मचारी सक्रिय रूप प्रतिक्रिया मांगते और स्वीकार करते हैं, उनके करियर में आगे बढ़ने की संभावना अधिक होती है। रचनात्मक आलोचना की स्वीकार करके, वे अपने कौशल की बढ़ा सकते हैं और प्रबंधकों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। हालांकि नौकरी की तलाश करना जनरेशन जेड की मानसिकता का हिस्सा है, लेकिन दीर्घकालिक करियर लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होने के लाभों को पहचानना महत्वपूर्ण है। वैसे जेनरेशन जेड भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लिहाजा उनकी तकनीकी दक्षता, उद्यमशीलता का सौच और मजबूत उपभोक्ता प्रभाव आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करेंगे। दीर्घकालिक सफलता के लिए जेनरेशन जेड को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होग, लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होगी और प्रोफेशन के प्रति नैतिकता को मजबूत करना होगा। ऐसा करने से वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकेंगे, आर्थिकी में मूल्यवान योगदान देंगे और कार्यबल में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकेंगे।

नौकरी बाजार के निरंतर परिवर्तन के बीच, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए ऐस कार्य वातावरण अनिवार्य है जो उत्पादकता, दक्षता व सामंजस्य को बढ़ावा दे। वहीं, नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे जेनरेशन जेड की विशिष्ट प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को समझें एवं ऐसा वातावरण तैयार करें जो तकनीकी अनुकूलन, कार्य-जीवन संतुलन व दीर्घकालिक विकास के अवसरों को प्रोत्साहित करे। यदि कर्मचारी और नियोक्ता एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जहाँ कर्मचारी जिम्मेदारी, प्रतिक्रिया और बफादारी को अपनाएं और नियोक्ता अनुकूलनशीलता, प्रेरणा एवं समर्थन प्रदान करें तो यह न केवल व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि व्यापक अर्थव्यवस्था और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।

कैसे हाथों के अनुभव युवा दिमाग के लिए सीखने को बदल रहे हैं

विजय गर्ग

अनुभवात्मक शिक्षा भारत में शिक्षा का चेहरा बदल रही है, जिससे युवा शिक्षार्थियों को विकास, जलवायु परिवर्तन और इतिहास जैसे जटिल विचारों की एक दिलचस्प समझ हासिल कर सकती है। हैंड्स-ऑन प्रदर्शन, कार्यशालाओं और भूमिका निभाने के माध्यम से, यह दृष्टिकोण न केवल समझ को बढ़ाता है, बल्कि 21 वीं सदी के कौशल को भी विकसित करता है। वे दिन जब छात्र बस अलगाव में सैद्धांतिक अवधारणाओं को याद करेंगे। अनुभवात्मक सीखने से युवा दिमाग के समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है क्योंकि यह छात्रों को करने के लिए सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कुछ भी-स्टेम प्रोजेक्ट्स, एआई, या यहां तक कि जीवन कौशल से संबंधित हो सकता है, इस तरह की चीज़ों को हाथों से लेकर दृष्टिकोण के माध्यम से महत्वपूर्ण सोच, समस्या को सुलझाने और रचनात्मकता के माध्यम से जोड़ा जाता है। विजय गर्ग के सीईओ, ₹यह सुनिश्चित करता है कि छात्र केवल जानकारी को भिगोने के लिए नहीं हैं, यह उस अभ्यास के बारे में जा रहा है, जिसके माध्यम से गहरी अंतर्दृष्टि और लागू व्यावहारिकता पकड़ लेती है,₹ पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों को सरल बनाना पारंपरिक शिक्षा तेजी से तकनीकी परिवर्तन के इस युग में एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि यह तेजी से बदलते, तेजी से वास्तविक दुनिया की अपेक्षाओं की मांग के साथ तालमेल रखने की कोशिश में वापस आ जाता है। अनुभवात्मक सीखना, हालांकि, पुल उस अंतर को पुल करता है। 21 वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना जैसे सहयोग, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच, अनुभवात्मक सीखने के लिए एक निरंतर बदलते रोजगार परिदृश्य में आवश्यक शिक्षार्थी के साथ

शिक्षार्थी। ₹गेट सेट लर्न पर हमारे सभी उत्पादों को सावधानीपूर्वक शिक्षार्थियों, विजय गर्ग में इन कौशल को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है अनुभवात्मक सीखने में पहुंच और समावेशिता इन परिवर्तनकारी अनुभवों को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया जाना है। ₹हमारे बीच डायनासोर₹ एक यात्रा प्रदर्शनी है जो मुंबई में शुरू होती है, लेकिन भारत के विभिन्न शहरों में जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मॉड्यूलर प्रोडक्शन डिज़ाइन इकट्ठा करना और फिर से इकट्ठा करना आसान बनाता है ताकि इसे एक स्थल और स्कूल से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। अनुभव को सस्ती बनाने के लिए, स्कूलों और मेजबान स्थानों के साथ सहयोग सीखें, यह सुनिश्चित करें कि टिकट की कीमतें यथासंभव कम रहें। दिलचस्प बात यह है कि प्रदर्शनी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। परिवार, और यहां तक कि एकल जाने वाले वयस्कों को प्रदर्शनी के आकर्षक विषय के लिए तैयार किया जाता है। जैसा कि गर्ग ने कहा, ₹अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पैलियोन्टोलॉजिस्ट द्वारा शोध निष्कर्ष, जिसने इस प्रदर्शन को प्रेरित किया, अपेक्षाकृत हाल ही में हैं और सभी आयु समूहों के लिए अपील करते हैं।₹ 21 वीं सदी के कौशल का एम्बेडिंग इस प्रदर्शनी में प्रत्येक क्षेत्र को आगंतुकों को सक्रिय रूप से संलग्न करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है। व्यक्ति कौशल को हल करने और अभ्यास करने से सीखता है, जैसे कि समस्याओं को हल करना और महत्वपूर्ण सोच। जानकारी के निष्क्रिय रिसीवर होने के बजाय, छात्र उन कार्यों में संलग्न होता है जो उनकी सामग्री को वास्तविक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षार्थियों को प्रदर्शनी में सभी डायनासोरों का नाम देने के लिए चुनौती दी जाती है, एक ऐसी गतिविधि जो आगंतुकों को हर विवरण पर उत्सुक होने के लिए उत्साहित करती है और प्रोत्साहित करती है। प्रदर्शनी का एक आकर्षण यूट्रानस की खोज है, जो एक पंख वाले डायनासोर है जो टायरानोसॉरस रेक्स के साथ एक वंश साझा करता है। यह विशेषता लोगों की जिज्ञासा को प्रभावित करती है क्योंकि वे आधुनिक पक्षियों के पूर्वजों के रूप में डायनासोर की कल्पना करते हैं। ₹एक पंख वाले डायनासोर को देखना कई शिक्षार्थियों के लिए खोज का एक अनुभव रहा है,₹ गरग ने शिक्षा और आश्चर्य को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए प्रदर्शनी की क्षमता पर कहा। अनुभवात्मक सीखना सिर्फ एक शिक्षण से बहुत अधिक है विधिः यह एक गतिशील भविष्य के लिए तैयार होने के लिए युवा मन के परिवर्तन के बारे में है। ₹हमारे बीच डायनासोर₹ जैसी पहल, जहां हाथों की गतिविधियों को अत्याधुनिक खोजों के साथ जोड़ा जाता है, क्या शिक्षा के बारे में क्या है-प्रेरणादायक जिज्ञासा, रचनात्मकता और सीखने के लिए एक आजीवन प्यार।

हिंसा की की परतें

विजय गर्ग

किसी स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे एक सुंदर झांकी के साथ जा रहे हों... उनमें सबसे आगे एक बच्ची 'भारत माता' बन कर तिरंगा हाथ में थामे चल रही हो.... उसके पीछे कुछ बच्चे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और 'अबला नहीं, सबला हैं हम' लिखी एक तख्ती थामे रानी लक्ष्मी बाई आदि महान विभूतियों के वेश में 'भारत माता' के जयकारे लगाते आगे बढ़ रहे हों... तो भावी पीढ़ी के इस आत्मविश्वास को देख कोई भी इंसान भावविभोर हो जा सकता है। मगर घर में टीवी पर चल रही खबरें देख कर कलेजा मुंह को आ सकता है, जिसमें यह बताया जाता है कि किसी पि ने गर्भवती पत्नी के पेट पर बैठ कर मुंह पर तकिया रख दिया और इस तरह उसकी हत्या कर दी । प्रहार इतना जोरदार था कि बच्चा गर्भनाल समेत बाहर आ गया और उसकी भी मौत हो गई । फिर इसी क्रम में अगली रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर आती है कि एक पूर्व सैनिक रहे पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर छोटे-छोटे टुकड़े कर उन्हें कुकर में उबाल कर पास के झील में फेंक आया। सवाल है कि स्कूल के बच्चों और उनमें भी भरोसे से भरी बच्चियों की आंखों में खिली उम्मीदों के बारे में कैसे खयाल आएंगे। किसी के भी मन पर मन पर भय और आशंकाओं के बादल छा जाना और मन विचलित हो जाना स्वाभाविक है ।

निर्ममता, संवेदनहीनता और स्वार्थ की भेंट चढ़ती महिलाओं की कहानियां बदस्तूर आज भी जारी हैं। इन कहानियों ने कई बार क्रूरता की चरम सीमा देखी है और नित नए कलेवर में आपराधिक मानसिकता वाले पुरुषों के बल प्रयोग की साक्षी बन रही हैं। इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि किसी गर्भवती महिला के पेट पर चढ़ कर उसका पति ही गला घोंट रहा होगा तो वह स्त्री और उसके गर्भ का वह बच्चा किस स्तर पीड़ा में होंगे। सिर्फ शक के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसा जघन्य कृत्य कर सकता है। खबरों के मुताबिक, दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और प्रेम में आने के बाद दोनों ने विवाह किया था। तो एक आम सामाजिक धारणा और सोच के अनुसार ऐसा लग सकता है कि सोशल मीडिया पर चढ़े प्रेम के रंग में सच्चाई ही कितनी होगी और इसीलिए लड़की को यह दुख भोगना पड़ा। मगर उसी शहर में हुई दूसरी घटना के संदर्भ में देखें तो माता-पिता ने फौजी लड़का खोज कर अपनी बेटी की शादी की थी। फिर उसके लगभग दस वर्ष बाद पत्नी को मार-काट कर उबाल कर फेंक देने की घटना को किस नजरिये से देखा जाएगा ? क्या यह ऐसी पहली घटना होगी जिसमें पति का दिमाग इतना खराब हो गया कि उसने हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए खूब दिमाग भी लगाया ? या फिर वह स्त्री लंबे समय से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही होगी और अपने बच्चे का मुंह देख, लोक लाज मर्यादा के भय से मौन रही होगी ?

विचित्र यह भी है कि ऐसे मामलों में लोक लाज का टोकरा भी पीड़िता के ही माथे सजाया जाता है, जिसे 'दोनों कुलों के 'लाज' को बचाए रखने के लिए मौन की घुट्टी परिवार और समाज द्वारा पिला दी जाती है। परिवार और समाज की नींद तब खुलती है, जब वह स्त्री दुनिया छोड़ चुकी होती है । उसके बाद भी वैसा कुछ उबाल देखने को नहीं मिलता जैसे किसी स्त्री द्वारा पुरुष की प्रताड़ना पर देश भर में आंदोलित मुखर प्रखर स्वरों जैसा हो । कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने आत्महत्या करते हुए अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर विस्तार से आरोप लगाया था, तब उसके लपेटे में पूरे स्त्री समाज को लिया गया। यही नहीं, इस घटना के हवाले से स्त्री को सशक्त करते देश के संविधान की कुछ धाराओं को भी कठघरे खड़ा करने की कोशिश हुई।

इसमें कोई दोराय नहीं कि हाल के दिनों में कुछ मामलों में पुरुष भी पीड़ित नजर आए हैं। दहेज के झूठे आरोप, तलाक के क्रम में मोटी रकम देने की वजह से मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना भी झेलते दिखे हैं। मगर अव्वल तो ऐसी घटनाओं की संख्या आज भी कम है, दूसरे ऐसी कई हिंसा की घटनाएं हैं, जिनकी पीड़ित स्त्री ही रही है। इतने प्रगतिशील समाज में तथाकथित रूप से 'चालाक स्त्रियों' के समाज में आज भी अकेले दहेज से रोज कम से कम बीस हत्या हो रही है। भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रपट में राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो के आंकड़ों का अध्ययन किया गया था। उसके मुताबिक, 2016 से 2021 के बीच देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की 22.8 लाख घटनाएं दर्ज की गईं और इनमें से सात लाख घटनाएं घरेलू हिंसा से संबंधित थीं। यानी तीस फीसद मामले पति और उसके परिवार द्वारा हिंसा के थे। इसमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना के आंकड़े शामिल नहीं है। ये आलम सरकारी आंकड़ों का है। दूरदराज के गांवों में कई निर्मम घटनाएं होंगी, जो पुलिस तक पहुंचाई भी नहीं जातीं। गरीब इलाकों में या तो कुछ ले-देकर लड़की के पक्ष को चुप कर दिया जाता है या लड़की पक्ष घर-परिवार की दूसरी लड़कियों के विवाह में आशंकित अड़चनों के भय से मुकदमा दर्ज करा कर किसी कानूनी पचड़े से बचते नजर आते हैं।

हलवा सेरेमनी से लाल कपड़े में लिपटे दस्तावेज तक, पढ़िए बजट की परंपरा और बदलाव की 9 खास बातें

परिवहन विशेष न्यूज

बजट 2025 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं। ब्रिटिशकालीन भारत से लेकर अब तक बजट के लंबे सफर में कई बदलाव हुए कई रस्में बदलीं तो कई नई रस्में जुड़ीं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहे भारत में बजट से जुड़े क्या बड़े बदलाव हुए। ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए यह स्टोरी।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। वे 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेंगी। बजट 1 फरवरी को जरूर पेश किया जाएगा, लेकिन इसकी तैयारियां काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। बजट से पहले इसे बनाने वाले खास अफसरों को बाहर की दुनिया से अलग रखा जाता है, हलवा सेरेमनी होती है। ऐसी ही कई रस्में लंबे समय से चली आ रही हैं। जबकि कुछ परंपराओं में बदलाव भी किया गया है, जैसे- बजट पेश करने का समय और तारीख। बजट में ये बदलाव क्या हैं और क्यों किए गए, पढ़िए ऐसे सभी सवालों के जवाब इस स्टोरी में।

बजट में हलवा बनाने की रस्म क्या है?

बजट से पहले हलवा बनाने की रस्म होती है। इस बार यह 24 जनवरी को आयोजित की गई। हर साल बजट से पहले हलवा सेरेमनी रखी जाती है। जो अधिकारी इस बजट को तैयार करते हैं, उन्हें इसे तैयार करने पर 'हलवा' परोसने की रस्म अदा की जाती है। इसी की साथ 'लॉक-इन पीरियड' शुरू हो जाता है।

दरअसल, भारत में किसी भी शुभ कार्य के दौरान मुंह मीठा कराने की परंपरा है। बजट के दस्तावेज तैयार हो जाने की खुशी में हलवा कढ़ाहे में बनाया जाता है और वित्त मंत्री की मौजूदगी में हलवा बजट बनाने वाले अफसरों और कर्मचारियों में बांटा जाता है। इसे हलवा सेरेमनी कहा जाता है।

बजट बनाने वाले अधिकारियों को लॉक करके क्यों रखा जाता है?

बजट बनाने वाली टीम के अधिकारियों को लोकसभा में बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में एक सप्ताह के लिए बंद रखा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि बजट से जुड़े कोई दस्तावेज लीक न हो जाएं।

पहले यह अवधि दो सप्ताह की थी। बजट बनाने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मोबाइल फोन भी ले लिए जाते हैं। इस अवधि में उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं होती है। वे अपने घर भी नहीं जा सकते हैं।

1 फरवरी को ही क्यों पेश किया जाता है आम बजट?

भारत सरकार का केंद्रीय बजट पहले 1 फरवरी के दिन पेश नहीं किया जाता था। बजट की यह तारीख आमतौर पर 28 फरवरी यानी फरवरी माह की अंतिम तारीख होती थी, लेकिन यह परंपरा साल 2017 में बदल गई। मोदी सरकार के तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने फरवरी अंत की बजाय 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा शुरू की। इस तरह ब्रिटिशकाल के समय से चली आ रही प्रथा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2017 में बदल गई।

तारीख बदलने की क्या थी वजह?

वित्त मंत्री ने बजट की तारीख 1 फरवरी करने के पीछे दो कारण बताए। पहला, बजट पेश करने और लागू होने के बीच कम समय अंतराल का होना। बजट मई माह में लागू होता है। ऐसे में 28 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को बजट पेश होने से अंतराल और ज्यादा मिल जाता है।

दूसरा, आम बजट में रेल बजट का विलय होना। पहले रेल बजट आम बजट से अलग पेश किया जाता था। अरुण जेटली ने कहा था कि विलय के कारण आम बजट को लागू होने के लिए नए नियम लागू करने और नए बदलाव के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

बजट पेश करने का समय बदलने के पीछे क्या है वजह?

अंग्रेजों की सुविधा के लिए आम बजट पहले शाम 5 बजे पेश किया जाता था। इसका कारण यह था कि जब भारत में शाम के 5 बजे होते थे, तब ब्रिटेन में दोपहर के करीब 12.30 बजे का समय होता था। अंग्रेजों के समय के हिसाब से भारत में शाम 5 बजे बजट पेश होता था।

1999 में जब अटलजी की सरकार सत्ता में आई, तब इस परंपरा को बदल दिया गया। अटलजी की सरकार के वित्तमंत्री यशवंतसिन्हा ने पहली बार शाम 5 बजे की जगह सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि 'भारत अब आजाद है, ब्रिटेन के अधीन नहीं है। इसलिए वह अपने हिसाब से समय तय कर सकता है। तभी से आम बजट सुबह 11 बजे पेश किया जा रहा है।

चमड़े के ब्रीफकेस की जगह लाल कवर में रखे जाने लगे दस्तावेज?

बजट फ्रेंच शब्द 'बौगेट' से बना है। इसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। पहले पैसे रखने के लिए इस थैले यानी बैग का उपयोग होता था। इसलिए वित्त विधेयक का नाम भी बजट ही पड़ गया। क्योंकि इसी चमड़े के थैले में बजट के दस्तावेज रखे जाते थे। स्वतंत्रता के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री थे आरके षनमुखम चेट्टी। वे भी अंग्रेजों की ही तरह चमड़े के बैग में बजट लेकर संसद आए थे। साल 2018 तक यह चमड़े के बैग या ब्रीफकेस की यह परंपरा कायम रही।

निर्मला सीतारमण ने बदली यह परंपरा

5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण ने इस परंपरा को बदल दिया। वे चमड़े के बैग की जगह लाल रंग के कपड़े में रखकर बजट के दस्तावेज लेकर संसद में आई थीं।

लाल रंग के इस कवर पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न 'अशोक स्तंभ' अंकित था। यह बदलाव भी पश्चिमी आजादी से बदलाव का प्रतीक माना गया।

लाल रंग के कपड़े के कवर में बजट को रखने के पीछे यह कहा गया कि यह बजट नहीं बल्कि हिंदू परंपरा के अनुसार बही-खाता है।

2021 में 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण लाल रंग के कपड़े में लिपटे बजट को 'टैबलेट' लेकर संसद पहुंची थीं।

1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सीतारमण ने 'पेपरलेस बजट' पेश किया था। वह लाल रंग के कपड़े के कवर में टेबलेट रखकर संसद पहुंची थीं।

वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से ही क्यों?

आमतौर पर 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत होती है। लेकिन वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, जो 31 मार्च तक चलता है। इसके पीछे कारण है भारत का फसल चक्र। भारत कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि बजट का मुख्य आधार हमेशा से रहा है। रबी की फसलों की कटाई आमतौर पर फरवरी और मार्च में होती है। ऐसे में किसानों के पास फसल बेचने के बाद पैसा मार्च में आना शुरू हो जाता है।

हमारी इकोनॉमी का 20 फीसदी हिस्सा अभी भी कृषि के क्षेत्र से ही आता है। दूसरा, ब्रिटेन का फाइनेंशियल ईयर भी 6 अप्रैल से प्रारंभ होता है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत में यही परंपरा लागू कर रखी थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2019 में वित्तीय वर्ष को बदलने की चर्चा भी चली थी, हालांकि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

वित्त विधेयक लोकसभा में ही किया जाता है पेश?

जानकार बताते हैं कि लोगों से प्राप्त टैक्स के जरिए सरकार के खजाने में राशि जमा होती है या निकाली जाती है। इसकी अनुमति संसद खासकर, लोकसभा से ली जाती है। यही कारण है कि बजट लोकसभा में ही पेश होता है। बजट लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है।

राज्यसभा इसमें कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन यह सुझाव मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसलिए वित्त विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए चला जाता है। राष्ट्रपति इसमें बदलाव नहीं करते हैं। उनकी भूमिका सिर्फ स्वीकार करके साइन करने तक सीमित है।

रेल बजट के मर्जर से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत?

देश के आर्थिक विशेषज्ञ और वित्त मामलों के जानकार डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने बताया

92 साल बाद क्यों टूटी रस्म, आम बजट में रेल बजट का हुआ मर्जर

पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाता था। साल 1924 से यह परंपरा चली आई, जो 2016 तक बनी रही। रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होने के पीछे सरकार का यह मानना था कि रेलवे एक बड़ा मंत्रालय है। यात्रा, ट्रांसपोर्टेशन और सुरक्षा की दृष्टि से इस बड़े मंत्रालय के बजट पर अलग से फोकस करना जरूरी है। इसलिए ये एकसाथ पेश होता रहा। 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रेल बजट आम बजट की अपेक्षा काफी छोटा है। इसलिए यह अलग से पेश करना सिर्फ एक रस्म अदायगी जैसा है। इसके बाद रेल बजट आम बजट के साथ जोड़ दिया गया।

वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे, 10 प्वाइंट में जानें खास बातें

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे (Budget Economic Survey 2025) पेश कर दिया है। इसमें रोजगार, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और जीडीपी ग्रोथ समेत कई पहलुओं पर दिलचस्प जानकारी मिली है। आइए इसे 10 प्वाइंट में समझते हैं।

कितनी रहेगी रियल जीडीपी ग्रोथ

आर्थिक सर्वे 2024-25 में घरेलू और वैश्विक स्तर पर मौजूद चुनौतियों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि विकास दर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8 फीसदी रहने का अनुमान दिया गया है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रोथ 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में अर्थव्यवस्था 8.4 फीसदी की तूफानी रफ्तार से बढ़ी थी।

रोजगार पर दिया गया खास जोर

आर्थिक सर्वे में सरकार ने रोजगार पर खास फोकस किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में बताया कि 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियों के अवसर के पैदा होंगे। घरेलू अर्थव्यवस्था का फोकस खासतौर पर सर्विस सेक्टर पर रहता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की कोशिश होगी।

89 लाख लोगों को मिला पीएम आवास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 89 लाख से अधिक घर बन चुके हैं। रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 बनाया है। इसने लाखों लोगों की शिकायतों का निपटारा किया, जिससे आम लोगों का भरोसा बढ़ा है।

महंगाई सरकार के लिए बनी बड़ी चुनौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में माना कि महंगाई सरकार और RBI के लिए महंगाई बड़ी चुनौती बनी हुई है। आरबीआई ने महंगाई को रोकने के लिए ही लंबे समय से ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। इसे भी अर्थव्यवस्था सुस्त की एक अहम वजह बताया जा रहा था।

कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट 3.5 फीसदी रही

कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट में सुधार देखने को मिल रहा है। इसकी वजह अनुकूल मौसम और नई तकनीक के साथ सरकारी कोशिश रही। किसानों को पीएम-किसान, डिजिटल एग्रीकल्चर और सिंचाई सुधार जैसी सरकारी योजना से किसानों को फायदा मिला। ड्रोन, सटीक कृषि (Precision Farming) और बेहतर क्वालिटी के बीज की वजह से पैदावार भी बढ़ी।

सर्विस सेक्टर में आया ज्यादा पैसा

आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर तक 29.8 अरब डॉलर FDI आया था। इसमें सबसे अधिक 5.7 अरब डॉलर का FDI सर्विस सेक्टर में आया। इससे जाहिर होता है कि विदेशी निवेशकों को सर्विस सेक्टर में ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं और वे इसमें ज्यादा पैसे लगा रहे हैं।

L&T चेयरमैन को लगेगा झटका! 60 घंटे से ज्यादा काम सेहत के लिए ठीक नहीं, आर्थिक सर्वे की भी मुहर

परिवहन विशेष न्यूज

कार्य संतुलन आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि एक हफ्ते में 60 दिन से अधिक काम करना मानसिक सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) की एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर अवसाद और चिंता के चलते सालाना लगभग 12 अरब दिन बर्बाद होते हैं। यह लगभग एक ट्रिलियन डॉलर के वित्तीय नुकसान के बराबर है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से भारत में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एलएंडटी के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने कुछ दिन पहले आम लोगों को हफ्ते में 90 घंटे काम करने की नसीहत दी थी। इस पर आर्थिक सर्वे में भी बात की गई है, जिसे शुक्रवार (31 जनवरी) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। आर्थिक में सर्वे में स्टडीज का हवाला देते हुए कहा गया कि एक हफ्ते में 60 घंटे से अधिक काम करने से सेहत पर काफी बुरा असर पड़ सकता है।

कामकाजी घंटे पर क्या बोला आर्थिक सर्वे?

इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि डेस्क पर लंबे समय तक बैठना मानसिक सेहत के लिए हानिकारक है। इसमें कहा गया कि जो शख्स डेस्क पर रोजाना 12 या इससे अधिक घंटे बिताते हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उनके तनाव में जाने का अंदेशा भी ज्यादा रहता है।

किस स्टडी का दिया हवाला

आर्थिक सर्वे में सैपियन लैब्स सेंटर फार ह्यूमन ब्रेन एंड माइंड की एक स्टडी का हवाला दिया। इसमें कहा गया, 'जो लोग डेस्क पर 12 या उससे अधिक घंटे बिताते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वे तनाव या अवसाद का शिकार भी हो सकते हैं।' वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) की एक स्टडी का हवाला देते हुए सर्वे में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर अवसाद और चिंता के चलते सालाना लगभग 12 अरब दिन बर्बाद होते हैं। यह लगभग एक ट्रिलियन डॉलर के वित्तीय नुकसान के बराबर है।

एक्सपर्ट की क्या है राय?

आर्थिक सर्वे पर टिप्पणी करते हुए शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की पार्टनर श्वेता श्राफ चोपड़ा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि यह कॉरपोरेट भारत में

मानसिक स्वास्थ्य संकट पर ध्यान नहीं देने के गहन आर्थिक प्रभावों को रेखांकित करता है। श्राफ ने कहा, 'वर्कप्लेस कल्चर को बेहतर करने से ना केवल सेहतमंद जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है, बल्कि कंपनी का मुनाफा भी बढ़ता है।'

L&T चेयरमैन ने क्या कहा था?

टेक्नोलॉजी से लेकर कंस्ट्रक्शन तक फैले ग्रुप लार्सन एंड टूब्रो (L&T) के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। सुब्रह्मण्यन ने कहा था, ₹आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं?₹। सुब्रह्मण्यन से पहले इन्फोसिस के फाउंडर एन नारायणमूर्ति भी कई बार एक हफ्ते में 70 घंटे काम की वकालत कर चुके हैं।

वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे, 10 प्वाइंट में जानें खास बातें

बजट आर्थिक सर्वेक्षण 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में विस्तार से बात की गई। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8 फीसदी रहने का अनुमान दिया है। आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे की खास बातें।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे (Budget Economic Survey 2025) पेश कर दिया है। इसमें रोजगार, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और जीडीपी ग्रोथ समेत कई पहलुओं पर दिलचस्प जानकारी मिली है। आइए इसे 10 प्वाइंट में समझते हैं।

कितनी रहेगी रियल जीडीपी ग्रोथ

आर्थिक सर्वे 2024-25 में घरेलू और वैश्विक स्तर पर मौजूद चुनौतियों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि विकास दर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8 फीसदी रहने का अनुमान दिया गया है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रोथ 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में अर्थव्यवस्था 8.4 फीसदी की तूफानी रफ्तार से बढ़ी थी।

रोजगार पर दिया गया खास जोर

आर्थिक सर्वे में सरकार ने रोजगार पर खास फोकस किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में बताया कि 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियों के अवसर के पैदा होंगे। घरेलू अर्थव्यवस्था का फोकस खासतौर पर सर्विस सेक्टर पर रहता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की कोशिश होगी।

89 लाख लोगों को मिला पीएम आवास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 89 लाख से अधिक घर बन चुके हैं। रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 बनाया है। इसने लाखों लोगों की शिकायतों का निपटारा किया, जिससे आम लोगों का भरोसा बढ़ा है।

महंगाई सरकार के लिए बनी बड़ी चुनौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में माना कि महंगाई सरकार और RBI के लिए महंगाई बड़ी चुनौती बनी हुई है। आरबीआई ने महंगाई को रोकने के लिए ही लंबे समय से ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। इसे भी अर्थव्यवस्था सुस्त की एक अहम वजह बताया जा रहा था।

कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट 3.5 फीसदी रही

कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट में सुधार देखने को मिल रहा है। इसकी वजह अनुकूल मौसम और नई तकनीक के साथ सरकारी कोशिश रही। किसानों को पीएम-किसान, डिजिटल एग्रीकल्चर और सिंचाई सुधार जैसी सरकारी योजना से किसानों को फायदा मिला। ड्रोन, सटीक कृषि (Precision Farming) और बेहतर क्वालिटी के बीज की वजह से पैदावार भी बढ़ी।

सर्विस सेक्टर में आया ज्यादा पैसा

आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर तक 29.8 अरब डॉलर FDI आया था। इसमें सबसे अधिक 5.7 अरब डॉलर का FDI सर्विस सेक्टर में आया। इससे जाहिर होता है कि विदेशी निवेशकों को सर्विस सेक्टर में ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं और वे इसमें ज्यादा पैसे लगा रहे हैं।

इनोवेशन को बढ़ावा देने पर फोकस

आर्थिक सर्वे में इनोवेशन को बढ़ावा देने पर फोकस करने की भी कही है। इसमें जोर दिया गया है कि इसके लिए सरकार को ही पहल करनी होगी। इसके लिए नीतिगत उलझनें कम करनी होगी। साथ ही, व्यवसायों को अपने कोर मिशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इससे इनोवेशन और कंपटीशन की भावना बढ़ सकती है।

EV के लिए विदेश पर निर्भरता घटाना

सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन पर काफी अधिक है। लेकिन, इनका प्रोडक्शन काफी हद तक इंपोर्ट पर टिका है। इससे देश का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। सरकार Make In India करके घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहती है। इससे लंबी अवधि में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बिजनेस आत्मनिर्भर हो सकेगा।

हाईवे और जल जीवन मिशन पर जोर

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान में 5,853 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। साथ ही, जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पाइप से पीने का पानी मिल चुका है।

वंदे भारत ट्रेन, रेल नेटवर्क विस्तार पर फोकस

आर्थिक सर्वे में रेलवे सेक्टर पर भी खास फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया गया। वहीं, अप्रैल और अक्टूबर 2024 के बीच वंदे भारत ट्रेनों के 17 नए पेयर शुरू किए गए।

38 फीसदी की दर से बढ़ा सरकारी खर्च

इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर काफी जोर दे रही है। वित्त वर्ष 2020 से लेकर 2024 तक सरकारी खर्च (capital Expenditure) 38.8 फीसदी की दर से बढ़ा है। हालांकि, लोकसभा चुनाव के चलते वित्त वर्ष 2025 में खर्च में कुछ कमी आई। यह चुनाव के बाद जुलाई से नवंबर 2024 के बीच बढ़ा है, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिला है।

मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में मिल सकती है बड़ी राहत, पीएम मोदी ने दिया संकेत

परिवहन विशेष न्यूज

बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इसमें उन्होंने संकेत दिया कि बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी जा सकती है। इसे इनकम टैक्स में छूट से जोड़कर देखा जा रहा है जिसकी मिडिल क्लास लंबे वक्त से मांग कर रहा है।

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत में मीडिया को संबोधित किया। इसमें उन्होंने संकेत दिया कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। पीएम मोदी ने इसके लिए धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आह्वान भी किया।

क्या इनकम टैक्स में मिलेगी राहत?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उनके बजट भाषण से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने खासतौर पर मिडिल क्लास का जिक्र करके अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बजट 2025 आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत देगा, जिसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।

वेतनभोगी करदाताओं को उम्मीद है कि बजट में इनकम टैक्स में कटौती, दरों में बदलाव और कर के बोझ को कम करने जैसी राहत मिल सकती है। टैक्स एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री भी नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब को और अधिक युक्तिसंगत बनाने और मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय देने के लिए मानक कटौती में बढ़ोतरी की वकालत कर रहे हैं।

किस टैक्स रिजीम में मिल सकती है छूट?

सरकार का पूरा फोकस अब न्यू टैक्स रिजीम पर है। इसलिए अगर कोई राहत मिलती है, तो वो नई टैक्स व्यवस्था में ही मिलेगी। वहीं, सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने पर भी विचार कर सकती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 72 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नई आयकर व्यवस्था को अपना लिया है।

क्यों मिल सकती है टैक्स में राहत?

केंद्रीय बजट 2025 ऐसे समय में पेश हो रहा है, जब जीडीपी ग्रोथ दो साल के निचले स्तर 5.4 फीसदी पर आ गई है। यही वजह है कि सरकार अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स रेट में कटौती कर सकती है। इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, जिसके खर्च से खपत को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक जानकार भी सरकार को यही रास्ता सुझा रहे हैं।

अमित शाह का पुतला जलाने में कानपुर के वकीलों के खिलाफ विवेचना में पुलिस के लिए सिर दर्द अधिवक्ता आर के सिंह के सवाल

सुनील बाजपेई

कानपुर। संविधान निर्माता डा.भीमराव अंबेडकर पर राज्यसभा में दिए गए विवादित बयान के विरोध में गृहमंत्री अमित शाह का पुतला जलाने के मामले में यहां वरिष्ठ अधिवक्ता आरके सिंह यादव और अन्य वकीलों के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराई गई एफ आई आर की विवेचना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

सूत्रों का दावा है यह भी है कि विवेचना को पूरी करने के रूप में आरोपी बनाए गए अधिवक्ताओं को दोषी साबित करते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट सीट लगाना भी सरल नहीं है ,क्योंकि पुलिस यानी विवेचक का पाला किसी ऐसे वैसे से नहीं बल्कि कानून की बारीकियों में भी बारीकियां खोजने वाले आर के सिंह यादव जैसे उन महारथी वरिष्ठ अधिवक्ता से पड़ा है, जो देश के बहुचर्चित रहे बेहमई कांड में दस्यु सुंदरी फूलन देवी के केस भी उसके पक्ष में अपने अकाट्य तर्को और अझेल जिरह से प्रबल विरोधियों के छक्के भी छुड़ा चुके हैं। यही नहीं बेहद निडर तथा हर किसी के सुख दुख में सदैव खड़े होने वाले शिवत्व स्वभाव के कानून विद वरिष्ठ अधिवक्ता आरके सिंह यादव असहाय गरीबों को भी हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में अग्रणी माने जाते हैं।

उनके मुताबिक दर्ज कराई गई एफ आई आर में जिस समय पुतला जलाने की बात कही गई है। उस समय वह वहां पर मौजूद नहीं रहकर इसी संदर्भ में अलग एक सभा को संबोधित कर रहे थे। जहां तक धारा 126 (2) BNS 2023 व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे का सवाल है। इसकी विवेचना दरोगा महेश सिंह के हवाले है और इस मुकदमे का संबंध राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में दिए गए बयान के विरोध में गृहमंत्री अमित शाह का पुतला जलाए जाने से है ,जिसके बारे में दरोगा गणेश द्वारा कोतवाली में दर्ज कराई गई एफ आई आर के मुताबिक 19.12.2024 को अधिवक्ता गण राहुल कनौजिया, रोहित सोनकर, बुद्ध चन्द, सागर यादव, डीएन पाल, वीरेन्द्र प्रताप, आर के यादव व आदि के एक समूह द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद भवन में बाबा भीम राव अम्बेडकर के उपर दिये गये एक वक्तव्य के विरोध में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला बना कर सार्वजनिक मार्ग को अवैध रूप से अवरुद्ध किया गया, जिससे सार्वजनिक यातायात व्यवस्था बाधित हो गयी तथा पुतले को बीच सड़क पर जलाते हुए सार्वजनिक सरकारी सड़क को क्षतिग्रस्त किया गया।

जहां तक दर्ज कराई गई एफ आई आर के आधार पर अधिवक्ताओं के खिलाफ सार्वजनिक मार्ग को अवैध रूप से अवरुद्ध करने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था बाधित होने तथा पुतले को जलाकर सार्वजनिक सरकारी सड़क को क्षतिग्रस्त करने आदि आरोपों को साबित करने का सवाल है। विवेचक के लिए यह सब कुछ बहुत सरल नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता आरके सिंह के मुताबिक विवेचना की परिभाषा को समझते हुए विवेचक को यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि अगर यातायात अवरुद्ध किया गया और लोगों को परेशानी हुई तो क्या उस परेशान राहगीर व्यक्ति ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई ? क्योंकि अगर किसी भी राहगीर को परेशानी हुई तो उसे रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। आखिर विरोध प्रदर्शन का और कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए यह भी सवाल करते हुए लोकहित में अपनी धुन के पक्के वरिष्ठ अधिवक्ता आरके सिंह यादव यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क कहां पर ,कैसे और कितनी क्षतिग्रस्त हुई विवेचना में यह भी अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर इस मामले में आरोपित अधिवक्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना बहुत सरल नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि सब कुछ की जाने वाली लिखा पढ़ी पर ही निर्भर करता है। यानी देश और समाज के हित में अधिकार सम्पन्न सक्षम पद का कोई भी धारक वह चाहे कार्यपालिका का हो, विधायिका का हो या फिर न्यायपालिका का ,किसी रूप में कुछ आदेशित न करें, कुछ कहे - बोले नहीं ,कुछ लिखे नहीं और मौन रहे तो फिर संसार का संचालन हो ही नहीं सकता। सारी व्यवस्था वहीं रुक जाएगी। मतलब अजर, अमर, अविनाशी अक्षरों से निर्मित शब्द से बने वाक्य ही लिखने, पढ़ने और बोलने के रुप में ही इस संसार का संचालन करते हैं, जिनका प्रयोग किये बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। खैर संसार संचालक अजर, अमर अविनाशी अक्षर से शब्द और शब्द से वाक्य लिखने के रूप में इस विवेचना का परिणाम किसके खिलाफ अथवा पक्ष में जाएगा। इसका सटीक जवाब चर्चित अधिवक्ता आरके सिंह के अलावा और कौन दे पाएगा।

बिना फिटनेस के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चल सकता। एटीएस प्रणाली पहली बार कटक में शुरू हुई

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेस्वर : अब बिना फिटनेस के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चल सकेगा। कटक में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) प्रणाली शुरू की गई है। पहले दिन 73 वाहनों का निरीक्षण किया गया। एटीएस प्रणाली, जिसे राज्य में सबसे पहले कटक में लांच किया गया था, का कल से ही परीक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण प्रक्रिया में चार पहिया से लेकर दस पहिया तक के वाहनों को शामिल किया गया है।पहले दिन परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर ने नाराज स्थित केंद्र का दौरा कर स्थिति का आकलन किया।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार वाहन फिटनेस परीक्षण के लिए एटीएस प्रणाली लागू की गई है। यह एटीएस जल्द ही राज्य में 21 और स्थानों पर स्थापित की जाएगी। इससे पहले यह कार्य वाहन पंजीकरण नवीनीकरण अधिकारियों के माध्यम से फिटनेस प्रमाण पत्र और रेटिंग के आधार पर किया जाता था। इस परीक्षण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए फिटनेस परीक्षण प्रणाली में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। इसलिए, जो वाहन सड़क पर चलने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एटीएस के माध्यम से स्वचालित रूप से रोक दिया जाएगा। परिवहन विभाग को जानकारी मिली है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी।

सुलतानपुर माजरा विधानसभा में लक्ष्मी जी की प्रचार ने मचाई धूम

सुलतानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में आज एक बड़ै राजनीतिक प्रचार का आयोजन किया गया, इस चुनाव प्रचार की अगुवाई लक्ष्मी जी ने की, जो कि रामदास आठवले की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) से इस क्षेत्र की प्रत्याशी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा, और उपस्थित भीड़ में गजब का उत्साह देखने को मिला।

लक्ष्मी जी के समर्थन में सुलतानपुर माजरा के लोग खुले दिल से सामने आए। चुनाव प्रचार में हर उम्र, जाति और वर्ग के लोग शामिल हुए, और लक्ष्मी जी को लेकर उनकी उम्मीदें साफ दिखी। इस चुनाव प्रचार से न केवल राजनीतिक माहौल को गर्म किया, बल्कि क्षेत्र में लक्ष्मी जी के प्रति लोगों के विश्वास को भी साबित किया।

सुलतानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में यह दृश्य काफी अलग था, जहां पर पार्टी और प्रत्याशी के प्रति जनता का समर्थन पहले कभी नहीं देखा गया। लक्ष्मी जी के समर्थकों ने चुनाव प्रचार रैली के दौरान जोश और जज्बे के साथ नारेबाजी की और क्षेत्र के विकास की उम्मीद जताई।

लक्ष्मी जी की रैली के दौरान उनकी नीतियों और योजनाओं को लेकर भी कई वादे किए गए, जिनमें खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे प्रमुख रहे। समर्थकों ने उम्मीद जताई कि लक्ष्मी जी इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी।

इस रैली ने साफ कर दिया कि सुलतानपुर माजरा विधानसभा में चुनावी माहौल तेज हो चुका है और लक्ष्मी जी की उम्मीदवारी को लेकर जनता का जोश देखने लायक है। अब यह देखना होगा कि क्या यह उत्साह आगामी चुनाव परिणामों में बदलता है।

दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने चुनाव का बाहिष्कार क्यों ना करा जाए? विषय पर सौंपा नोटिस

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के टैक्सी बसों के मालिकों को 10 सालो से हो रहीं समस्यायों पर केंद्र और दिल्ली सरकार (सांसदों /विधयाको) द्वारा ध्यान ना देने के कारण 2025(दिल्ली विधान सभा) का चुनाव का बाहिष्कार क्यों ना करा जाए? इसका एक नोटिस श्री राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिसन ऑफ़ इंडिया को दिया

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शी संजय सम्राट का कहना हैं की हम दिल्ली के टैक्सी बसों मालिक, लगातार 10 सालो से केंद्र सरकार और

दिल्ली सरकार और उसके मंत्रियो और सांसदों /विधायको से उपेक्षित रहें हैं इन सब ने इन 10 सालो में ना तो मिलने का सही से समय दिया और कभी कभार बड़ी मुश्किल से इन्होने मिलने का समय भी दें दिया तो

हमारी जायज मांगो को इन्होने रद्दी की टोकरी में डाल दिया.

हमारी मुख्य मांगे थी :-

1:- दिल्ली की आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से 80 किलो प्रति घंटा की स्पीड लिमिट हटना चाहिए.

क्योंकि इस स्पीड लिमिट की वजह से एक्सप्रेस वे और हाई वे पर भी हमारी टूरिस्ट टैक्सी बसें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकती जबकि सारी प्राइवेट गाड़ियों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा हैं.

2:- दिल्ली में पेनिक बटन के नाम पर करोडो रूपया का घोटाला हो रहा हैं और अब इसका नाम बदल कर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस रख कर टैक्सी बसों वाले से 16 हजार रुपये प्रति गाडी द्वारा दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बनाये गए पेनल में प्राइवेट कम्पनी द्वारा लिया जा रहा हैं. जिसमे पेनिक बटन दबाने से कुछ नहीं होता जबकि ये महिलाओ की सुरक्षा के लिए टैक्सी बसों में लगाया जाता हैं, ये एक तरह से मात्र 5 रुपये का प्लास्टिक का बटन हैं जिसकी कीमत हमें 16 हजार से भी ज्यादा देनी पडती हैं.

3:- कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मेनेजमेंट द्वारा बी एस 3/4 डीजल पेट्रोल की टैक्सी बसों को प्रदूषण की आड़ में हर साल बंद करा कर इन गरीब टैक्सी बसों के चालक /मालिकों से 20 हजार का जुर्माना वसूल किया जाता रहा हैं. जबकि प्रदूषण के दुसरे कारण जैसे कंस्ट्रक्शन की धुल मिट्टी और पराली जलाने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते. ना हीं दिल्ली एनसीआर में उड़ने वाले हवाई जहाज का प्रदूषण चेक करा जाता हैं, जबकि दिल्ली में हजारों हवाई जहाज रोज आते हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं? आज तक ना तो सरकार ने और ना ही CAQM ने कृत्रिम बारिश कराई हैं.

4:- इसी तरह प्रदूषण की आड़ में डीजल गाड़ियों को 10 साल में और पेट्रोल गाड़ियों को 15 सालो स्क्रैप (कूड़ा) बनाया जा रहा हैं.

या घर घर जाकर घरों से जबरजस्ती दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी दिल्ली के हर कोने से गाड़िया छीन रहे है.

आज तक सरकार ने या कमिसन फॉर एयर क्वाल्टी मैनेजमेंट (CAQM) ने हवाई जहाज की 10 या 15 साल उम्र तय नहीं की? ना हीं उन्हें दिल्ली एनसीआर से बाहर भेजा?

5:- दिल्ली में पंजीकृत सारी कमर्सल गाड़ियों से नाजयाज MCD टोल टैक्स वसूला जा रहा हैं. उसके लिए प्राइवेट कम्पनी से नाजयाज टैक्स वसूला जा रहा है.

6:- दिल्ली में झुल झुली फिटनेस सेंटर में गाड़ियों की फिटनेस कराने के लिए महीने की वेटिंग है. जिसकी वजह से हजारों टैक्सी बसें बगैर फिटनेस के पार्किंग में खड़ी हैं.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पुछा हैं की आप 2025 के चुनाव को पर्व की तरह बता रहें हैं. हम आपसे ये जानना चाहते हैं की कड़कती सर्दी में में लाइनों में लग कर हम विधायक /सांसदों को चुनते हैं जिससे ये बाद में सरकार बनाकर ये सब एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ कर हमसे मिलते तक नहीं हैं और अगर किसी कारण से मिल भी गए तो ये हमारी मांगो को कार्यन्वित नहीं करते बल्कि सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह देते हैं, अगर हमें अपने सारे काम सुप्रीम कोर्ट से ही कराने हैं तो हमें लाइन में लग कर चुनाव में वोट देने की क्या जरूरत हैं?

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, संजय सम्राट ने पत्र के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त से पुछा की हम 2025 के चुनाव में वोट क्यों डाले ?या अगर वोट करें तो आगे 5 सालो में ये सरकार और चुने विधायक /सांसद हमारा काम करेंगे या हमें मिलने का समय देंगे इसकी गारंटी कौन लेगा?

ये विधायक चुनाव किसी और पार्टी से लड़ते हैं और जितने के बाद जनता का विश्वास तोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं. क्या ऐसे विधायक /सांसद को विधानसभा / लोक सभा से बर्खास्त नहीं करना चाइये? ये पूरे 5 साल सड़के या सीवर या सवच्छ पानी या अन्य कोई कार्य नहीं करते. क्या सरकार द्वारा दी गई 5 साल की तनख्वाह इनसे वापिस नहीं लेनी चाहिए??

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय भी माँगा हैं जिस से उनसे मिलकर और फिर दिल्ली के लाखों टैक्सी बस मालिक /चालाक से बात करके हम चुनाव बहिष्कार का फैसला करेंगे की हमें मतदान करना हैं या नहीं??? या इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार क्यों ना करा जाए?

क्योंकि इस समय दिल्ली एनसीआर के टैक्सी /बस मालिकों /चालकों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लाखों लोगो में बहुत रोष हैं।

आया बसंत पंचमी का पर्व...!

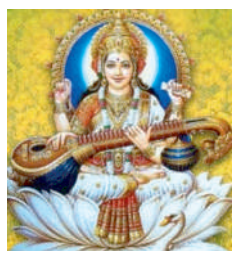

आया है बसंत पंचमी का पर्व,
करों खुशियों का संचार गर्व।
इस दिन का है विशेष महत्व,
भारतीय संस्कृति का है सत्व।
करो देवी सरस्वती आराधना,
ज्ञान, संगीत व कला साधना।

आया है बसंत पंचमी का पर्व,
करों खुशियों का संचार गर्व।
स्वयं को उमंग, ऊर्जा से भरों,
अहसांस सबको देते हुए चलो।
आज बदलते है प्रकृति के रंग,
खुशी और समृद्धि कर दे दंग।

आया है बसंत पंचमी का पर्व,
करों खुशियों का संचार गर्व।
छाई हरियाली पीला है बसंत,
सारी सृष्टि खिली हुई अनंत।
समाज, राष्ट्र, विश्व की नमन,
करें महिमा यशगान मनमोहन।

संजय एम तराणेकर

महाकुंभ से तीर्थ स्थान करके बापूजी नगर बोईनपल्ली लोटे यात्रियों का फुल मालाओ से किया भव्य स्वागत

जगदीश सीरवी

हैदराबाद। महाकुंभ से तीर्थ स्थान करके बापूजी नगर बोईनपल्ली सिकंदराबाद लोटे यात्रियों का बैंड बाजे व जुलूस के साथ भव्य स्वागत किया गया इस अवसर पर गायत्री देवी-मांगीलाल, सायरी देवी- ओम प्रकाश , प्रेमा - डुंगाराम , दुर्गा, मनीषा, रिया सोलंकी

इंदिरा देवी - रूघाराम , प्रेमा- जगदीश , हितेश गहलोत , मूली देवी- नवला राम, लीला देवी- कूकाराम पंवार, मसरी देवी वरफ़ा एवं अन्य।

केजरीवाल ने हाई अमोनिया वाला पानी पर चुनाव आयोग की दूसरी नोटिस का दिया जवाब, कहा- दिल्लीवासियों को बधाई, हम सबका संघर्ष रंग लाया

सुषमा रानी

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के दूसरी नोटिस का जवाब दे दिया। चुनाव आयोग ने हरियाणा से दिल्ली में भेजे जा रहे हाई आमेनिया युक्त पानी को लेकर दिए बयान पर उनसे जवाब मांगा था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि हम सबका संघर्ष रंग लाया। दिल्ली में जो ज़हरीला पानी भेजा जा रहा था, वो अब बंद हो गया। दिल्ली में आने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा 7 पीपीएम से घटकर 2 पीपीएम हो गई है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाते और संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली की आधी आबादी को पानी नहीं मिल रहा होता। हमने दिल्ली को बहुत बड़े पानी के संकट से बचा लिया। चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस देकर सज़ा देने की धमकी दी है। मैंने चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं कि आज आम आदमी पार्टी, हमारी सरकार और दिल्ली के ढाई करोड़ लोगों का संघर्ष सफल हुआ और सकारात्मक नतीजा लाया। 26-27 जनवरी तक हरियाणा की सरकार दिल्ली में जो हरियाणा पानी भेज रही थी, आज वह 7.2 पीपीएम अमोनिया से 2.1 पीपीएम पर आ गया है। 2.1 अमोनिया के साथ हमारे अधिकतर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक चल सकते हैं और लोगों को ठीक-ठाक पानी मिल सकता है। हम सब के संघर्ष की वजह से पानी में अमोनिया का स्तर नीचे आया। इससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली में त्राहि-त्राहि मचाने के लिए अमोनिया वाला पानी भेजा था। अगर उनका इस पर कंट्रोल नहीं होता तो पानी में अमोनिया का पीपीएम अचानक बढ़ कैसे गया और शोर करने पर यह अचानक घट कैसे गया?

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि चुनाव आयोग ने मुझे एक नोटिस भेजा था। मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर चुनाव आयोग ने मुझे दूसरा नोटिस भेजा। चुनाव आयोग के दूसरे नोटिस में जो भाषा लिखी है, उससे ऐसा लगता है कि वह पहले से ही तय कर चुके हैं कि क्या सजा सुनानी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बहुत संगीन है। मैं मोटे-मोटे तौर पर दिल्ली और देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है? लगभग दिसंबर के महीने से दिल्ली की सीएम आतिशी ने यह देखा कि दिल्ली में यमुना के जरिए जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया बढ़ने लगा है। हम पानी के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए दिसंबर से जनवरी तक दिल्ली सरकार और यहां तक की पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत कोशिश की कि बातचीत के जरिए समाधान निकले।

अशोकनगर NFC स्थित सेपटा परिवार द्वारा महिला संगीत व अतिथियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित

परिवहन विशेष न्यूज

अशोकनगर NFC स्थित सेपटा परिवार द्वारा आयोजित महिला संगीत व अतिथियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित आयोजक श्री आईजी गौशाला सह सचिव ढगलाराम सेपटा , हुकमाराम सेपटा ,हिमताराम, प्रवीण, लक्ष्मण, CA नेमीचंद सीरवी समाज पारसीगुटा बडेर अध्यक्ष मोहनलाल हाम्बड़, शिक्षा समिति पारसीगुटा बडेर अध्यक्ष लाबुराम पंवार , सीरवी समाज मल्लापुर बडेर अध्यक्ष तुलसाराम सिन्दडॉ, श्री आईजी गौशाला अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, सचिव हुकमाराम सानपुरा , कोषाध्यक्ष नारायण लाल परिहार, आईजी सेवा संघ अध्यक्ष भगाराम मुलेवा, आईजी सेवा संघ कोषाध्यक्ष बाबूलाल मुलेवा, नारायण लाल गेहलोत,चेनाराम परिहार, अर्जुनलाल बर्फा, कालुराम काग ,किशनसिंह राठौड़, रामलाल परिहार, चैनाराम परिहार, बाबूलाल मुलेवा, भंवरलाल मुलेवा, मोतीलाल काग,विकास शर्मा,हापुराम गेहलोत ,ओमप्रकाश पंवार , मंगलाराम सेपटा, मांगीलाल, धर्मीचंद सोलंकी, नेमीचन्द्र हाम्बड़, दुर्गाप्रसाद हाम्बड़,सुरेश सैणचा,राजुराम चोयल, पवन हाम्बड़,माधुराम चोयल, कानाराम ,आनंद शर्मा, नरेश खण्डेलवाल , कैलाश शर्मा, किशोर शर्मा, व समाज बंधु

हैदराबाद स्थित सिन्दडॉ व परिहार परिवार द्वारा आयोजित चिल्कानगर अतिथियों के सम्मान समारोह में कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य पदाधिकारियों आयोजक रमेश सिन्दडॉ , हेमाराम परिहार,सीरवी समाज तेलंगाना कोरेमुला बडेर सचिव डायाराम लचेटा, तेजाराम, सीरवी समाज तेलंगाना बालाजी नगर,श्री आईजी गौशाला अध्यक्ष मंगलाराम पंवार,सह सचिव ढगलाराम सेपटा, सीरवी समाज मल्लापुर बडेर अध्यक्ष तुलसाराम सिन्दडॉ,सीरवी समाज मल्लापुर बडेर सह सचिव सुरेश सैणचा, कोषाध्यक्ष नेमाराम हाम्बड़, ओमप्रकाश पंवार व समाज बंधु।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023